HP/129/SML/2019-2021 Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500 01-15 अक्तूबर, 2019

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

हिमाचल, वर्ष 2/ अंक 30/ पृष्ठ: 16 मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

निष्ठा सही हो और निरंतर प्रयासरत रहे तो सफलता क़दम चूम ही लेती है: डॉ॰ एल.सी. शर्मा

आईआईआरडी लगातार दूसरी बार सीएसआर में नंबर वन

बेहतरीन ई-शिक्षा प्रणाली में लहराया परचम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आईआईआरडी ने सीएसआर के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की । लगातार दूसरी बार 'सर्वश्रेष्ठ एनजीओ' का खिताब हासिल किया है। संस्था ने इस बार यह उपलब्धि **वचुर्अल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम** के तहत बेहतरीन ई शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में हासिल की है जबकि बीते वर्ष झारखंड में जनजातीय महिलाओं को प्रोजेक्ट रूपांतरण के तहत अजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए उतकृष्ठ संस्था के तौर पर आईआईआरडी को सीएसआर टाइम्स की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। आईआईआरडी को यह सम्मान दिल्ली में हाल ही में आयोजित '6वें नेश्नल सीएसआर सम्मिट, सीएसआर टाइम्स अवार्ड एंड 49वें इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2019' कार्यक्रम मे प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सीएसआर टाइम्स और इंडियन अचीवर्स फोरम के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न पीएसयू, कॉरपोरेट और गैरसरकारी संस्थाओं की ओर से सीएसआर के तहत किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला गया और उसके बाद बेहतर कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इन सभी में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं की फेहरिस्त में आईआईआरडी का नाम सबसे ऊपर रहा।

गृह राज्यमंत्री कृष्ण रेड्डी ने बतौर मुख्यअतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम की शुरूआत की। सांसद विरेंद्र कुमार बतौर विशेष अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, ऑल इंडिया कांउसिल फॉर टैक्निकल एजूकेशन के अध्यक्ष डाक्टर सहासराबुद्धे, इंडिया अर्चीवर्स फोरम के निदेशक लीशा गोयनका, सीएसआर टाइम्स के संपादक हरीश चंद्रा भी कार्यक्रम में खास तौर पर मौजूद रहे।

इंडिया अर्चीवर्स फोरम के सचिव रवि शंकर ने कार्यक्रम की जानकारी दी और अथितियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने जम्मू कश्मीर में सीएसआर गतिविधियों के आयोजन पर बल देते हुए विभिन्न संस्थाओं से इस दिशा में कार्य करने का आह्वाहन किया। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्थाओं की भी सराहना की साथ ही ई लर्निंग में बेहतर कार्य करने के लिए आईआईआरडी को विशेष तौर पर बधाई दी। आईआईआरडी हिमाचल प्रदेश की इकलौती ऐसी संस्था है जो प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। यही कारण है कि सीएसआर टाइम्स की ओर से आईआईआरडी के कार्यों को हमेशा सराहा जाता है और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्यप्रणाली के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जाता है। इसी कड़ी में इस बार भी सीएसआर टाइम्स ने आईआईआरडी को शिक्षा के क्षेत्र में नंबर वन आंकते हुए बेस्ट एनजीओ यानी बेहतरीन स्वंय सेवी संस्था के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है।

शिक्षा के क्षेत्र में आईआरआडी का चयन क्यों :

आईआईआरडी हिमाचल की ऐसी पहली संस्था है जो पेपरलैस कार्यप्रणाली को वास्तव में कार्यान्वित कर रही है। संस्था की ओर से कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के बाद हिमाचल में भी ई लर्निंग पर विशेष तौर पर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न विषयों के छात्रों को ऑनलाइन ट्यूटोरियल ट्रेनिंग देने की योजना पर कार्य शुरू हो चुका है। योजना के पहले चरण में आईआईआरडी की ओर से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी तक 70 से अधिक प्रशिक्षुओं को वचुर्अल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (वीएलएमएस) पद्वति से प्रशिक्षण दिया जा चुका है जबकि करीब इतने ही प्रशिक्षुओं को इसी पद्वति से विभिन्न कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण जारी है। इस तरह के पद्वति में प्रशिक्षु महज एक स्मार्ट फोन की सहायता से कौशल विकास की ऑनलाइन ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है। वीएलएमएस पद्वति से ई लर्निंग के क्षेत्र में ही आईआईआरडी को सर्वश्रेष्ठ संस्था आंकते हुए सीएसआर टाइम्स ने बेस्ट एनजीओ अवार्ड से नवाजा है।

आगे क्या...

NSDC के प्रशिक्षार्थियों के बाद अब आईआईआरडी सीबीएससी 10वीं के गणित विषय को लेकर वीएलएमएस के तहत ई लर्निंग मॉड्यूल तैयार कर चुका है। जल्द ही प्रदेश के विभिन्न छात्रों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई है। गौरतलब है कि हिमाचल में छात्रों को गणित को आसानी से समझने मे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह बात खुद शिक्षा विभाग के सर्वे में सामने आती रही है कि दूर दराज के क्षेत्रों मे अक्सर गणित के अध्यापकों की कमी और अन्य कारणों से छात्र गणित और विज्ञान में पिछड़ जाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए आईआईआरडी ने पहले चरण में गणित विषय को ई लर्निंग के तहत चुना है। जल्द ही दूसरे विषयों पर कार्य किया जाएगा। बहरहाल अगर किसी भी छात्र को गणित समझने में परेशानी हो रही है तो वह सीधे ऑनलाइन आईआईआरडी से वचुर्अल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़कर अपने सवाल का हल जान सकता है। इस मॉड्यूल के तहत गणित के सवालों को आसानी से समझने के तरीके समझाए जाएंगे और विद्यार्थी की समझने की क्षमता के अनुरूप ही उसे समझाया जाएगा।

दूसरे राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में आईआईआरडी:

हिमाचल के अलावा आईआईआरडी देश के दूसरे राज्यों में भी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। आईआईआरडी की ओर से कर्नाटक के धारवाड़, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मध्य प्रदेश के सागर और विदिशा में विभिन्न स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज चलाई जा रही है। इनमें छात्रों को कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ट दिए गए हैं ताकि वे आसानी से पाठ्यक्रम की जटिलताओं को समझ सके।

क्या कहते है आईआईआरडी के प्रबन्ध निदेशक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आईआईआरडी ने सीएसआर के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इसके लिए आईआईआरडी की पूरी टीम बधाई की पात्र है । हम विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं । जल्द ही हिमाचल मे भी शिक्षा के क्षेत्र मे आईआईआरडी एक नया आयाम स्थापित करेंगी।

मिशन रीव अब जनरल इंश्योरेंस में देगा सेवाऐं

एस बी आई जनरल इंश्योरेंस के साथ होगी भागीदारी

SBI General INSURANCE

द रीव टाइम्स: हेम राज चौहान

मिशन रीव अपने दस महत्वपूर्ण अनुभागों के माध्यम से ग्रामीण सेवाओं में निरंतर प्रयासरत है । इसमें लोगों के जीवन को सुरक्षित और स्वयं व परिवार के भविष्य को उज्जवल करने के लिए मिशन रीव द्वारा एल आई सी के साथ मिलकर जीवन बीमा क्षेत्र में सेवाऐं दी जा रही है । अब मिशन रीव में एस बी आई जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी लोगों तक पहुंचने की सफल कोशिश की गई है । लोगों को उनके घरद्वार पर ही सेवाओं को ले जाने के लिए मिशन रीव आज सबसे बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है । जीवन बीमा के क्षेत्र में दी गई सेवाओं के साथ अब लोगों को जनरल बीमा की उपलब्धता गुणवत्ता के साथ दी जा रही है ।

- वाहन, निजी वाहन का बीमा,
- प्रॉपर्टी बीमा,
- स्वास्थ्य बीमा,
- गंभीर बीमारी बीमा,
- आरोग्य टॉप-अप बीमा,
- आरोग्य प्लस बीमा,
- आवास बीमा,
- दुर्घटना बीमा, आदि में समस्त क्षेत्रों में मिशन रीव सेवाऐं प्रदान कर रहा है ।

कैसे सेवाऐं देगा मिशन रीव

मिशन रीव गांव-गांव में आज एक जाना जाने वाला नाम है । सरकार के सहयोगी के रुप में मिशन रीव सदैव अग्रणी भूमिका में रहा ही है लेकिन अपनी नायाब सेवाओं के माध्यम से भी लोगों तक विश्वसनीय पहुंच बनाई है । उपरोक्त बीमा सेवाओं को मिशन रीव के कार्यकर्ता गांव-गांव में लोगों को जागरुक करेंगें तथा उनका उनकी आवश्यकतानुसार बीमा करवाऐंगें । मिशन रीव का फील्ड स्टाफ इसे करने से पहले प्रशिक्षण को प्राप्त करेंगे । यानि उनको क्या करना है और पूरी प्रक्रिया को प्रशिक्षण के माध्यम से बताया जाऐगा । प्रशिक्षण लेने के बाद एस बी आई जनरल इंश्योरेंस के साथ गांव में लोगों को जानकारी दी जाऐगी तथा इसके लिए जागरुकता शिविर आदि भी लगाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है ।

RURALIZING INDIA - EMPOWERING VILLAGE RIEV

कि दुनिया देखती रह जाए

MISSION RIEV

Ruralising India - Empowering Villages

website: www.missionriev.in

या दूरभाष न. -0177-2640761, 2844073 पर संपर्क करें

स्वास्थ्य सेवाओं में हिमाचल बन रहा है अव्वल : निदेशक

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में दिनों-दिन प्रगति पर है तथा हम देश के गिने-चुने राज्यों में से एक हैं जहां लोगों को बेहतर एवं सुविधाजनक तरीके से स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान करने के प्रति सरकार कृतसंकल्प है । निदेशक स्वास्थ्य विभाग डॉ० अजय कुमार गुप्ता ने द रीव टाइम्स को दिए साक्षात्कार में ये बातें कहीं । उन्होंने माना कि अभी भी डॉक्टर की कमी और कुछ अन्य मुद्दों पर स्वास्थ्य विभाग को और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है फिर भी हिमाचल में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति है । उन्होंने द रीव टाइम्स के अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया और विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों को भी समाचार पत्र के साथ साझा किया । साक्षात्कार का विस्तृत विवरण आप पृष्ठ संख्या 10 पर विस्तार से पढ़ सकते हैं ।

शेष पृष्ठ 10 पर...

मिशन रीव के दो वर्ष पूरा होने पर आईआईआरडी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई । पिछल दो वर्ष में आप सभी के सहयोग से हम आज इस मुकाम पर आए है जिसे पूरे भारत में आज मिशन रीव को एक अलग पहचान मिली है साथ ही प्रदेश और देशभर से सभी के सहयोग के लिए हार्दिक आभार । आपकी समस्त चिंताओं के समाधान का नाम ही मिशन रीव है ।

आसाम में आईआईआरडी शुरू कर रहा स्मार्ट क्लास रूम बेहतर और गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर सराहनीय पहल

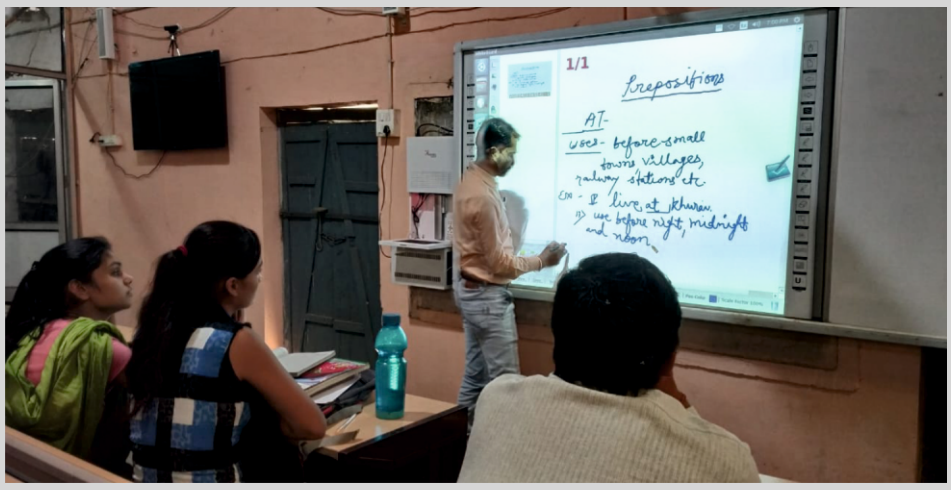

द रीव टाइम्सः हेम राज चौहान

आई आई आर डी के स्मार्ट क्लास रुम पर भारत के विभिन्न राज्यों में किए गए प्रयासों को सराहना मिल रही है । इसी प्रयास में अब आसाम में भी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए संस्था स्मार्ट क्लास रुम शुरु करने जा रही है ।

- आरंभिक तौर पर आसाम के 30 विद्यालय इससे लाभान्वित होंगे ।
- इन स्कूलों में 60 स्मार्टक्लास रुम स्थापित किये जा रहे हैं । इससे सरकारी विद्यालयों के बच्चों को गुणवत्ता तथा तकनीकि शिक्षा का लाभ मिल सकेगा।
- स्मार्ट क्लास रुम में अत्याधुनिक तकनीक से लर्निंग करवाई जाएगी । कंप्युटर, बोर्ड, कैमरा आदि से लैस ये रुम उच्च स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा ।
- आसाम में अंग्रजी और असमिया भाषाओं का प्रयोग होगा । इसमें सरकारी स्कूल तो शामिल हैं ही साथ ही ग्रामीण क्षेत्र और दूर-दराज के क्षेत्र भी शामिल है जहां के बच्चे इसका लाभ उठा पाऐंगे । पढ़ाई के अनुभव को और अधिक गुणवत्ता आधारित करने व तकनीक का सदुपयोग करना भी इसका एक बड़ा उद्देश्य है ।

विदित हो कि आईआईआरडी भारत के विभिन्न राज्यों में लगातार इस प्रकार के स्मार्ट क्लास रुम गेल इंडिया के सौजन्य से स्थापित करने की सफल कोशिश में है । इससे पूर्व कर्नाटक के धारवाड़ में 40, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 20 तथा मध्यप्रदेश के सागर और विदिशा में 20 स्मार्ट क्लास रुम स्थापित कर प्रशंसनीय प्रयास कर चुका है । इसके बाद अब आसाम में भी इसे शुरु किया जा रहा है । अन्य राज्यों में भी भविष्य में इस प्रकार के स्मार्ट क्लास रुम शुरु करने की योजना है ।

Establishment of Smart Classrooms

It is the need of the hour that our schools should upgrade themselves and get abreast with the outer world, IIRD proposed to establish Smart / Digital Classrooms in Govt Schools of Karnataka to make the future of our country well-versed, cracking the nutshell and making students more creative and inventive.

Project Establishment of Digital Classrooms in 20 Government schools in District Dharwad, supported by **GAIL India Ltd,** aimed at enhancing teaching and learning by technology as the prime teaching tool. Smart-boards are a lot smarter when it comes to field trips, which are impossible with textbooks. A field trip to the deserts of Sahara or the rainforest of the Amazon basin becomes easy with visuals in the smart-boards of smart classroom. These visuals are definitely more attractive than those descriptions in a few lines of a textbook.

गेल इंडिया के तत्वावधान में स्मार्ट क्लास रूम से भारत वर्ष में आईआईआरडी ने की सराहनीय पहल

द रीव टाइम्सः हेम राज चौहान

आईआईआरडी विगत कुछ वर्षों से शिक्षा की नई तकनीक पर कार्य करते हुए स्मार्ट क्लास रुम स्थापित कर नए आयाम स्थापित कर रहा है ।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्मार्ट क्लास रूम :

उद्देश्य :

- उत्तर प्रदेश के वाराणसी के 20 सरकारी विद्यालयों में 20 डिजीटल/स्मार्ट क्लास रुम की स्थापना
- विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को क्षमता संवर्द्धन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के मध्य बेहतरीन संवाद एवं माहौल तथा स्वस्थ चर्चा का वातावरण तैयार करना।
- विद्यार्थियों को बेहतरीन जानकारी एवं पढ़ाई के लिए ऑनलाईन सामग्री उपलब्ध करवाना ।
- इस परियोजना के स्थाइत्व प्रदान करने के लिए आवश्यक पहल

इस परियोजना का महत्व :

- ऑनलाईन/डिजीटल पढ़ाई से बच्चों को चार दीवारी की उस परंपरागत व्यवस्था से हटाकर एक नवीन और तीव्रता से मानसिकता पर प्रभाव डालने वाला वातावरण तैयार करना । इससे न केवल लेखन अपितु भाषा प्रवाह भी बढ़ेगा ।
- यह ऑन लाईन प्रक्रिया प्रशिक्षकों/शिक्षकों को एक बेहतरीन और सुविधाजनक तरीके को प्रदान करता है ।
- दृष्य और श्रवण दोनों की श्रेणी में उत्तम सुविधा के साथ प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है जिससे एक स्वस्थ माहौल में लाभप्रद चर्चा हो सकती है ।
- अब समय आ गया है कि हमारे शिक्षण संस्थान अपग्रेड हो और ऑनलाईन/डिजीटल शिक्षा से स्वयं को इतना क़ाबिल बना लें कि प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी किसी से भी कम न हो । इतना ही नहीं अपने मस्तिष्क का विकास करने के साथ ही नये विचार और क्रियाशीलता का विकास हो सके ।
- बजाए इसके कि बोर्ड पर डॉयग्राम या ड्राईंग आदि बनाने में समय व्यर्थ गंवाया जाए, स्मार्ट क्लास में ये सब पूर्व से ही अंकित हैं जिससे सीखने में भी आसानी होती है तथा समय की बचत भी होती है ।
- स्मार्ट बोर्ड किताबों से कहीं अधिक सुविधाजनक एवं स्मार्ट है । इससे विद्यार्थियों को किताबों के बोझ से मुक्ति मिलेगी ।

स्मार्ट क्लास रूम में आवश्यक उपकरण

क्रम संख्या	उपकरण
1	परस्पर संवादात्मक/ interactive वॉइट बोर्ड
2	डी टी डी
3	यू पी एस पॉवर सिस्टम
4	मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर
5	हिन्दी माध्यम के लिए राज्य बोर्ड विशयवस्तु
6	ऐंप्लीफायर
7	ऐक्सेसरीज के लिए केबिनेट व्यवस्था
8	स्पीकर बॉक्स
9	यू पी एस व बैटरी के लिए रैक आदि
10	विद्युत केबल, विद्युत प्वाइंट व यूपीएस केबल

गेल
GAIL

गेल (इंडिया) लिमिटेड सी एस आर कार्यक्रम के अंतर्गत
डिजिटल क्लास रुम की स्थापना वर्ष 2018-19

IIRD
हम जानते हैं गाँव को बेहतर

Implemented by: IIRD – www.iirdshimla.org
Institute for Integrated Rural Development
एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान
हम जानते हैं गाँव को बेहतर

स्मार्ट क्लासरुम

शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पहल करते हुए आईआईआरडी ने कनार्टक के हुबली में 40 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए हैं। इसमें कन्नड़ भाषा में सभी विषयों को डिजीटाइज किया गया। इसके साथ ही इंटरेक्टिव बोर्ड के माध्यम से इन विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। इस प्रयास से बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चों के साथ अध्यापकों की अध्यापन क्षमता में भी प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। अभी 40 और विद्यालयों को स्मार्ट क्लासेज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जारी है।

विश्व धर्म चेतना मंच का नशे पर जागरूकता कार्यक्रम

हम अपनी मौत का सामान ले चलें.....श्रीनिवास जोशी

धूम्रपान में मानवीय बॉम्ब है सिगरेट ..स्वयं के अलावा औरों को भी देती है धीमी मौत

द रीव टाइम्स : हेम राज चौहान

दिल में छुपाके प्यार का तूफान ले चले, हम अपनी मौत का सामान ले चलें.....इस पंक्ति से नशे के ख़िलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार एवं प्रशासनिक अधिकारी श्रीनिवास जोशी ने सरस्वती विद्या मंदिर, विकासनगर में धुम्रपान के प्रति नई पीढ़ी को जागरुक किया । श्रीनिवास जोशी ने कहा कि जब मैं किसी को बोलता हूं कि बीड़ी-सिगरेट मत पीयो तो वो कहता है कि इससे क्या होगा? क्या हम कभी नहीं मरेंगे? तो मैं बोलता हूं कि मरना तो शाश्वत है । लेकिन अपनी वास्तविक मौत से 10 वर्ष पूर्व मर जाओगे । उन्होंने कहा कि आज धूम्रपान से युवा ज़िंदगी छिन्न-भिन्न हो चुकी है । देश में 39 प्रतिशत व्यस्क सीगरेट पी रहे हैं । यानि लगभग 39 करोड़ लोग इसका शिकार है । केवल धुम्रपान से ही लगभग 10 लाख लोग प्रतिवर्ष मर रहे हैं । सरकार ने कोटपा 2003 कानून के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान पर प्रतिबंद लगाया है । बावजूद इसके देश में प्रति सेंकड, प्रति मिनट धुम्रपान करने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है ।

श्रीनिवास जोशी ने विद्यार्थियों से कहा कि वो तीन ' नहीं ' को गांठ बांध कर रख लें ।

- सार्वजनिक स्थल पर धुम्रपान नहीं
- 18 वर्ष से कम आयु के युवाओं को नशीले पदार्थ बेचना और खरीदना नहीं
- परोक्ष और अपरोक्ष रुप से किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं होगा

इसके अलावा यह तय है कि बीड़ी-सिगरेट शिक्षण संस्थानों से 100 गज की दूरी होना आवश्यक है । उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 5000 लोग सिगरेट पीना शुरु करते हैं । 3000 लोग प्रतिदिन मर भी रहे हैं । उन्होंने इस बात पर ज़ोर देकर कहा कि सेकेंड हैंड स्मोक मानवीय बंब है....42 प्रतिशत बच्चे इसका शिकार है क्योंकि उनके घर पर उनके पिता या अन्य धुम्रपान करते हैं और वो अनचाहे ही इसका शिकार होते हैं । इससे ये बच्चे परेशान है और मानसिक तौर पर असफल भी हैं ।

संस्था के अध्यक्ष नंदी वर्धन जैन ने सरस्वती विद्या मंदिर के प्रशासन और प्रधानाचार्य का आभार जताते हुए कहा कि आज बच्चों को इस नशे की बीमारी से दूर रहने के लिए माता-पिता और गुरुजनों की एक बड़ी भूमिका है । उन्हें समय-समय पर समुचित देख-रेख करने की आवश्यकता है । बच्चों का अनुचित व्यवहार बताता है कि नशे ने किस कदर युवाओं को अपनी चपेट में ले लिया है ।

उन्होंने कहा कि वो सभी बच्चों से प्रतिज्ञा चाहते हैं कि वो विश्व धर्म चेतना मंच के इस अभियान का हिस्सा बनें और इसके लिए हम बार-बार स्कूल में आकर जागरुकता कार्यक्रम करते रहेंगे । प्रधानाचार्य लेखराज ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उनके विद्यालय में इस गंभीर मुद्दे पर इतने विद्वान लोग अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं । उन्होंने इसके लिए संस्था और आगंतुकों को धन्यवाद किया ।

उन्होंने द रीव टाइम्स का भी आभार जताया और आईआईआरडी की नशामुक्त हिमाचल की भी तारीफ की । कार्यक्रम में नंदी वर्धन जैन, श्रीनिवास जोशी, रोशन लाल जैन, कुशल और द रीव टाइम्स के संपादक हेम राज चौहान ने भी भाग लिया ।

आईजीएमसी प्रबंधन के विरोध में उतरी सीटू

द रीव टाइम्स

सीटू जिला कमेटी शिमला ने आईजीएमसी प्रबंधन व रेनबो सिक्योरिटी एंटरप्राइज की तानाशाही के खिलाफ आईजीएमसी के बाहर मुंह पर काली पट्टियां बांधकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सीटू राज्याध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, उपाध्यक्ष जगत राम, बलबीर पराशर, चन्द्रकान्त वर्मा, पवन, राज्य सचिव रमाकांत मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष किशोरी ढटवालिया, जिला सचिव विनोद बिरसांटा, बालक राम,हिमी देवी,रामप्रकाश,सतपाल बिरसांटा आदि मौजूद रहे।

प्रदर्शन के दौरान ही आईजीएमसी के प्रधानाचार्य डॉ मुकन्द लाल ने सीटू प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए आमंत्रित कर लिया । लगभग दो घण्टे चली बातचीत में एसडीएम शहरी,डीएसपी शहरी,आईजीएमसी के प्रबंधन से जुड़े विभिन्न डॉक्टर मौजूद रहे। आईजीएमसी के प्रधानाचार्य ने सीटू जिला कमेटी दिये गए मांग-पत्र पर सकारात्मक पहलकदमी का आश्वासन दिया।

सीटू राज्याध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,राज्य उपाध्यक्ष जगत राम,राज्य सचिव रमाकांत मिश्रा,राज्य कमेटी सदस्य किशोरी ढटवालिया, विनोद बिरसांटा, बालक राम, रामप्रकाश, हिमी देवी ने चेताया है कि अगर छः महिला सुरक्षा कर्मियों पर एकतरफा कार्रवाई हुए तो सीटू सड़कों पर उतर आएगा। उन्होंने कहा कि रेनबो प्रबंधन छः महिला सुरक्षा कर्मियों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा है। आईजीएमसी व रेनबो प्रबंधन इन छः निर्दोष महिला सुरक्षा कर्मियों का स्थानांतरण करने की साजिश रच रहा है जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आईजीएमसी अराजकता का केन्द्र बना हुआ है। पिछले 10 दिनों में तमाम घटनाओं के सूत्रधारों को बचाया जा रहा है। आईजीएमसी प्रबंधन को इन सूत्रधारों की अराजकता के सारे तथ्य जमा किये गए हैं परन्तु उन पर कार्रवाई करने के बजाए उनका संरक्षण किया जा रहा है व निर्दोष महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इन अराजक तत्वों की साजिशों की ऑडियो क्लिप व स्क्रीनशॉट प्रशासन को दिए गए हैं परन्तु प्रशासन व प्रबंधन उन पर कोई कार्रवाई करने के बजाए निर्दोष महिलाओं की प्रताड़ना कर रहा है।

स्मोक फ्री राजधानी शिमला पर खुली स्वास्थ्य महकमे की पोल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

स्वास्थ्य विभाग को भले ही शिमला सिटी को स्मोक फ्री किए जाने को लेकर अवार्ड मिले हों लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। स्कूल परिसर से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन एक चौथाई विक्रेता अभी भी इस दायरे के भीतर बीड़ी और सिगरेट बेच रहे हैं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के कम्यूनिटी मेडिसन और गायनाकोलॉजी की ओर से किए सर्वे में यह खुलासा हुआ है। नशे बेचने वाले सरेआम कोटपा एक्ट 2003 की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

सर्वे के मुताबिक शहर के 32 ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिनके सामने 157 प्वाइंटों पर तंबाकू बिक रहा है। प्रदेश सरकार ने भले ही दुकानदारों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना करने का प्रावधान कर रखा हो लेकिन 100 मीटर दायरे में अभी भी नशा बेचने पर अंकुश नहीं लग पाया है। प्रदेश सरकार ने नशे पर रोक लगाने के लिए शहरों में तरह-तरह के कार्यक्रम चला रखे हैं। आए दिन नशे के खिलाफ रैलियां तक निकाली जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल प्रशासन और स्कूल कॉलेजों तथा एमबीबीएस के छात्रों ने कई नशा मुक्त अभियान चलाए जाते हैं, बावजूद इसके नशा बेचने पर पाबंदी नहीं लग पा रही। स्कूलों में छात्रों को नशे के खिलाफ पाठ पढ़ाया जा रहा है। प्रतिदिन अध्यापक नशे से शरीर पर होने वाले कुप्रभाव के बारे में जानकारी देते हैं लेकिन 100 मीटर के दायरे में नशा बेचने पर अंकुश नहीं लग रहा है। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि स्कूलों के आसपास नशा नहीं बेचने दिया जाएगा। कहा कि नशे पर रोक लगाने के लिए छापेमारी की जाएगी।

नगर निगम की मनमर्जी के ख़िलाफ हल्ला बोल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शिमला नागरिक सभा ने पानी व गारबेज की दरों मे की गई वृद्धि के खिलाफ नगर निगम के महापौर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नागरिक सभा ने चेताया है कि अगर जनता की लूट बन्द न की गयी तो नागरिक सभा जनांदोलन के जरिए जनता के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेगी।

नागरिक सभा अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व सचिव कपिल शर्मा ने कहा है कि गारबेज क्लेक्शन की दरों मे हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि दर किसी भी रूप में मान्य नहीं होगी । उन्होंने कहा कि शिमला शहर में पानी की दरों में भारी वृद्धि व सीवरेज सेस के नाम पर भारी लूट की जा रही है। मर्ज एरिया के लोगों द्वारा सभी तरह के टैक्स देने के बावजूद भी उन्हें महंगी दरों पर पानी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मर्ज एरिया के लोगों से कमर्शियल दरों पर पानी के बिल बसूलने बन्द किया जाए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बिलों के माध्यम से गरीब जनता पर और ज़्यादा बोझ पड़ना तय है। एक तरफ नगर निगम पानी व कूड़े की दरों में भारी वृद्धि कर रही है वहीं दूसरी ओर किरायेदारों पर मकान मालिकों की और से और ज्यादा बोझ लादा जाना तय है।

उन्होंने कहा कि जब से भाजपा शाशित नगर निगम सत्ता में आई है, शहर में विकास के बजाए जनता की जनसुविधाओं की दरों में भारी वृद्धि करके उन पर लगातार हमला किया जा रहा है। यह नगर निगम बिना अच्छी सेवा के भारी यूजर चार्ज की परंपरा को मजबूत करना चाहती है जिसे किसी भी सूरत में माना नहीं जाएगा। यह नगर निगम कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। इसी मुहिम के तहत पानी व कूड़े के निजीकरण की साजिशें रची जा रही हैं। शिमला में शिमला कल प्रबंधन निगम लिमिटेड के गठन करके नगर निगम की शक्तियों को कमजोर किया गया है व पानी के निजीकरण की पटकथा लिखी जा रही है। यह नागरिक सभा को कतई मंजूर नहीं है। यह नगर निगम जनता पर आर्थिक बोझ डालने वाला नगर निगम है। पानी व सीवरेज की दरों में बढौतरी के बाद एक बार फिर भाजपा शासित नगर निगम ने यह साबित कर दिया है कि वर्तमान नगर निगम जनता विरोधी है। नागरिक सभा ने मांग की है कि गारवेज कलेक्शन की दरों में हर साल दस प्रतिशत बढोतरी का निर्णय तुरन्त वापिस लिया जाए। सभा ने यह भी मांग की है कि पानी की दरों में की गई बढ़ोतरी वापिस ली जाए । सभा ने मांग की है कि सीवरेज सेस को पूरी तरह समाप्त किया जाए। इस धरने में नागरिक सभा अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा,सचिव कपिल शर्मा, बलवीर पराशर,अजय दुलटा,चन्द्रकान्त वर्मा,किशोरी ढटवालिया, विवेक कश्यप, हिमी देवी, प्रियंका,कविता,रुचिका, विनोद बिरसांटा, बालक राम,पवन शर्मा,रमन थारटा, बंटी, विक्रम बग्गा, अनिल ठाकुर, आकाश पालसरा, अनिल नेगी, रामप्रकाश, विरेन्दर, अनिल पँवार, गौरव, अंकित, नोख राम, जगत, रंजीव कुठियाला व रामु खैरालिया आदि मौजूद रहे।

शारदीय नवरात्रे 2019

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नवरात्रि यानि की नौ रातें। शरद नवरात्रे (Sharad Navratri) हिन्दुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक हैं जिसे दुर्गा पूजा (Durga Puja) के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के सभी नौ रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के नौ दिनों को बेहद पवित्र माना जाता है। इस दौरान लोग देवी के नौ रूपों की आराधना कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। मान्यता है कि इन नौ दिनों में जो भी सच्चे मन से मां दुर्गा की पूजा करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह पर्व बताता है कि झूठ कितना भी बड़ा और पाप कितना भी ताकतवर क्यों न हो अंत में जीत सच्चाई और धर्म की ही होती है।

शारदीय नवरात्रि कब हैं?

शारदीय नवरात्रि को मुख्य नवरात्रि माना जाता है। हिन्दू कैलेंडर के अनुसार यह नवरात्रि शरद ऋतु में अश्विन शुक्ल पक्ष से शुरू होती हैं और पूरे नौ दिनों तक चलती हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार हर साल सितंबर-अक्टूबर के महीने में आता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 29 सितंबर से शुरू होकर 07 अक्टूबर तक हैं। 08 अक्टूबर को विजयदशमी या दशहरा मनाया जाएगा।

नवरात्रो का महत्व

हिन्दू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। साल में दो बार नवरात्रि पड़ती हैं, जिन्हें चैत्र नवरात्रे (Chaitra Navratri) और शारदीय नवरात्रे (Sharad Navratri) के नाम से जाना जाता है। जहां चैत्र नवरात्र से हिन्दू वर्ष की शुरुआत होती है वहीं शारदीय नवरात्रे (Shardiya Navratri) अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। यह त्योहार इस बात का द्योतक है कि मां की ममता जहां सृजन करती है। वहीं, मां का विकराल रूप दुष्टों का संहार भी कर सकता है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा मनाए जाने के अलग-अलग कारण हैं।

मान्यता है कि देवी दुर्गा ने महिशासुर नाम के राक्षस का वध किया था। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में नवरात्र में नवदुर्गा की पूजा की जाती है। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि साल के इन्हीं नौ दिनों में देवी मां अपने मायके आती हैं। ऐसे में इन नौ दिनों को दुर्गा उत्सव के रूप में मनाया जाता है।

शारदीय नवरात्रो की तिथियां

29 सितंबर 2019	नवरात्रि का पहला दिन, प्रतिपदा, कलश स्थापना, चंद्र दर्शन और शैलपुत्री पूजन।
30 सितंबर 2019	**नवरात्रि का दूसरा दिन, द्वितीया, बह्मचारिणी पूजन।**
01 अक्टूबर 2019	नवरात्रि का तीसरा दिन, तृतीया, चंद्रघंटा पूजन।
02 अक्टूबर 2019	**नवरात्रि का चौथा दिन, चतुर्थी, कुष्मांडा पूजन।**
03 अक्टूबर 2019	नवरात्रि का पांचवां दिन, पंचमी, स्कंदमाता पूजन।
04 अक्टूबर 2019	**नवरात्रि का छठा दिन, षष्ठी, सरस्वती पूजन।**
05 अक्टूबर 2019	नवरात्रि का सातवां दिन, सप्तमी, कात्यायनी पूजन।
06 अक्टूबर 2019	**नवरात्रि का आठवां दिन, अष्टमी, कालरात्रि पूजन, कन्या पूजन।**
07 अक्टूबर 2019	नवरात्रि का नौवां दिन, नवमी, महागौरी पूजन, कन्या पूजन, नवमी हवन, नवरात्रि पारण
08 अक्टूबर 2019	विजयदशमी या दशहरा

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

प्लास्टिक के खिलाफ ऊना में चला अभियान

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

पॉलीथीन मुक्त अभियान में उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने सिविल सोसाइटी का सहयोग मांगा है। उपायुक्त ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रहे लोगों से घर जाकर मुलाकात की और उन्हें जिला प्रशासन की ओर से तैयार करवाए जा रहे कपड़े के बैग भेंट किए। संदीप कुमार ने सभी से पर्यावरण संरक्षण के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। उपायुक्त ने हिमोत्कर्ष संस्था के प्रदेशाध्यक्ष कंवर हरि सिंह, पर्यावरणविद ओसी शर्मा, समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े डॉ. हरजिंदर, वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी सत्य मित्र बक्शी, प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोमेश कुमार शर्मा तथा एपीएमसी चेयरमैन बलवीर बग्गा से मुलाकात की। उपायुक्त ने सभी को कपड़े के बैग भेंट करते हुए कहा कि पॉलीथिन का इस्तेमाल बंद करने में समाज के सभी वर्गों का सहयोग महत्वपूर्ण है। दो अक्तूबर से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित होने जा रहा है, इसीलिए प्रशासन ने प्लास्टिक के विरुद्ध जागरूकता अभियान छेड़ा है।

कालाअंब स्कूल से पांच शिक्षक पाए नदारद

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

सिरमौर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कालाअंब के निरीक्षण के दौरान उपनिदेशक ने पांच अध्यापकों को नदारद पाया। इसको लेकर उपनिदेशक ने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी है। जानकारी के अनुसार जब उपनिदेशक उच्च शिक्षा दिलबर जीत चंद्रा कालाअंब स्कूल के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। ठीक 9 बजे वह स्कूल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 11 बजे तक स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस बीच पांच शिक्षक स्कूल से नदारद रहे। शिक्षकों ने स्कूल से कोई अवकाश नहीं लिया था। विभाग के अनुसार स्कूल से तीन पीजीटी, एक टीजीटी और एक उर्दू शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। इसको लेकर उपनिदेशक ने स्कूल प्रबंधन को कड़ी फटकार भी लगाई। शिक्षा उपनिदेशक ने अचानक ही स्कूल में दबिश दे दी। इस दौरान

उन्होंने कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से सवाल जवाब भी किए।

साथ ही स्कूल की समस्याओं को लेकर भी संज्ञान लिया। इससे पहले शिक्षा उपनिदेशक राजकीय कन्या स्कूल नाहन के साथ-साथ अन्य स्कूलों की औचक निरीक्षण कर चुके हैं। उच्च शिक्षा उपनिदेशक ने बताया कि कालाअंब स्कूल से पांच शिक्षक नदारद पाए गए हैं। शिक्षकों ने कोई छुट्टी नहीं ली थी। स्कूल से बेवजह नदारद रहने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट निदेशक शिमला को भेज दी है।

पॉलिथीन मिलने पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने वसूले 11500

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक पांवटा की टीम ने पांवटा, मिश्रवाला और माजरा क्षेत्रों में छापामारी की। इस दौरान प्रतिबंधित पहलिथीन मिलने पर दुकानदारों और संस्थानों के संचालकों को 11,500 रुपये जुर्माना भी ठोका। खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक पांवटा ने बताया कि उन्हें शिकायतें मिल रही थीं कि क्षेत्र में अभी भी कुछ दुकानदार और व्यापारी प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल चोरी छिपे कर रहे हैं। इस पर

पांवटा, मिश्रवाला और माजरा क्षेत्रों में औचक निरीक्षक किया गया। इस दौरान करीब 20 दुकानों का निरीक्षण किया गया, इसमें 8 दुकानों-संस्थानों में पॉलिथीन मिला है। इन व्यापारियों को 11,500 रुपये की राशि बतौर जुर्माना वसूली गई है। टीम ने मौके से प्लास्टिक, गिलास और प्लेटों को भी कब्जे में लिया गया। फूड इंस्पेक्टर ने कहा कि पांवटा और आसपास क्षेत्रों में इस तरह के निरीक्षण भविष्य में भी जारी रहेंगे।

लोगों का स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ फूटा गुस्सा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

दून हलके की पहाड़ी पंचायत गोयला के शेरला और अंबोटा के ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग के प्रति रोष व्यक्त किया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग चंडी के उप स्वास्थ्य केंद्र सेरला को 30 वर्ष पहले स्वीकृत किया गया था। 15 वर्षों तक यहां पर नियमित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई गईं लेकिन इसके बाद से यहां पर ताला लटका हुआ है। हैरानी की बात यह है कि हर जनता के चुने हुए एक भी नुमाइंदे ने यहां के लोगों की सुध लेने की जहमत नहीं उठाई। हाल ही में आपकी आवाज पट्टा महलोग के बैनर तले महलोग विकास मंच के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने उक्त गांव का दौरा किया और यहां के लोगों के हालात की जानकारी ली। राजकुमार उर्फ राजू शर्मा ने बताया कि यहां के लोग आज भी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं।

यहां न तो स्वास्थ्य की कोई सरकारी सुविधा है और न ही सड़क की सुविधा है। यदि कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो 10 किलोमीटर दूर गोयला, पट्टा या घरेड़ तक चारपाई पर मरीज को उठाकर ले जाना पड़ता है। इसके इलावा रास्ते में एक तेज बहते हुए पानी का नाला पड़ता है जिसके ऊपर कोई पुल तक नहीं है। बरसात के बाद पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो जाता है जिसके कारण छोटे बच्चों और महिलाओं को नाला पार करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छठी से आठवीं तक एक शिक्षक के सहारे चल रहा स्कूल पिछली सरकार के दौरान अंतिम वर्ष में पांचवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक स्कूल को अपग्रेड तो कर दिया गया। यहां पर न तो बच्चों को बैठने के लिए कमरों का निर्माण करवाया और न ही अध्यापकों की व्यवस्था। एक शिक्षक के सहारे प्राइमरी स्कूल के एक कमरे में छठी से आठवीं कक्षा के बच्चे पढ़ाई करते हैं। स्थानीय निवासी कुलदीप ठाकुर, श्रवण कुमार, चमन लाल, भगत राम, शिव लाल, यशपाल आदि ने सरकार से गांवों की समस्याओं को महलोग विकास मंच के अध्यक्ष राजू शर्मा से प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उठाने की मांग की है।

नए अस्पताल भवन में बनेगा हेलीपैड, एयर एंबुलेंस सुविधा से जोड़ने की तैयारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

कथेड़ में 70 बीघा जमीन पर बनने वाले नए अस्पताल में एयर एंबुलेंस की सुविधा मरीजों को देने की तैयारी है। यहां हेलीपैड बनाकर मरीजों को रेफर मामलों की स्थिति में हेलीकॉप्टर से दिल्ली या चंडीगढ़ भेजा जा सकेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर ली है।

अस्पताल के साथ शॉपिंग कांपलेक्स भी बनाया जाएगा ताकि मरीजों और तीमारदारों को बेहतर सुविधा दी जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने कई आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से कार्य शुरू कर दिया है। इसे अन्य अस्पतालों से बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अस्पताल में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टाफ मुहैया करवाने की तैयारियां कर रहा है। नए क्षेत्रीय अस्पताल भवन की क्षमता 300 बिस्तर होगी जिसमें 50 बिस्तर का ट्रॉमा सेंटर भी होगा। निशानदेही के बाद भूमि की चारों ओर फेंसिंग कार्य की पहल की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग इस अस्पताल को भूकंपरोधी और दिव्यांग फ्रेंडली बनाने की तैयारी पहले ही कर चुका है। इससे लोगों को भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की संभावना बढ़ी हैं।

पटवारी के 69 पदों पर भर्ती, 30 सितंबर तक करें आवेदन

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

राजस्व विभाग ने पटवारी के 69 पद अधिसूचित किए गए हैं। इसके लिए 12वीं पास अभ्यर्थी 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिला रोजगार अधिकारी अनीता गौतम ने बताया कि इन पदों के लिए आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 18 से 45 वर्ष जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 18 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है। अनीता गौतम ने बताया कि पटवारी के 69 पदों में 40 पद सामान्य वर्ग, 10 पद अनुसूचित जाति वर्ग, 5 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग और 14 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग में अनारक्षित श्रेणी के 28, सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के 7, सामान्य स्पोर्ट्समैन श्रेणी के 4, सामान्य भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के एक पद पर भर्ती होगी। जबकि अनुसूचित जाति श्रेणी के 10 पदों में से अनुसूचित जाति के 6, अनुसूचित जाति भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में 3 व अनुसूचित जाति स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित श्रेणी में एक पद के लिए आवदेन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति के पांच पदों में अनारक्षित श्रेणी के तीन और अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के 2 पदों जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 पदों में से ओबीसी श्रेणी के 11 पदों, ओबीसी आईआरडीपी के 1 पद और ओबीसी भूतपूर्व

सैनिक श्रेणी के 2 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योग्य और इच्छुक उम्मीदवार संपूर्ण प्रमाण पत्र लेकर संबंधित रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवाकर इन पदों के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आने आवेदन 30 सितंबर तक डीसी कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

लैब डायग्नोसिस को तीन लाख के बजट का प्रावधान

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

प्रथम रेफरल यूनिट अस्पताल दौलतपुर की रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की सालाना बैठक हाल में हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम गगरेट ने की। इसके अलावा गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। दो घंटे चली बैठक में दौलतपुर अस्पताल प्रभारी सदस्य सचिव रोगी कल्याण समिति डॉ. नीरू नरूला ने साल 2019–2020 के अनुमानित बजट 31 लाख 21 हजार 500 सौ रुपये पेश किया। इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। डॉ. नीरू नरूला ने वर्ष 2018–19 में अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए उठाए कदमों और आय-व्यय का लेखाजोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने मरीजों की सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए किए जाने-वाले कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लैब डाइग्नोसिस के लिए तीन लाख के बजट का प्रावधान किया है। अस्पताल में एपीएल, बीपीएल मरीजों के लिए दवाइयों के लिए दो लाख के बजट रखा है। बिजली एवं पानी की व्यवस्था के लिए एक लाख 50 हजार का बजट प्रस्तावित है। रिपेयर एवं मेंटिनेस के लिए दो लाख का प्रावधान किया गया। कलेक्शन एवं डिस्पोजेबल के लिए 60 हजार के बजट का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा अस्पताल के लिए मशीनरी खरीद के लिए 72 हजार का प्रावधान किया है। अस्पताल में टेस्ट और एक्सरे के दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई। इसके अलावा मातृ शिशु एवं बीपीएल परिवारों की मुफ्त दवाइयों के लिये 10 लाख रुपये बजट में रखे गए हैं। अस्पताल में बिजली बिल के लिए एक लाख 80 हजार, अस्पताल में मरम्मत, पानी व्यवस्था और अन्य रखरखाव के लिए छह लाख का प्रावधान किया गया है। बायो मेडिकल वेस्ट के लिए 60 हजार रुपये मिलेंगे। वरिष्ठ नागरिकों और बीपीएल परिवारों के लिए एक लाख 48 हजार 856 रुपये की दवाइयां एवं टेस्ट फ्री किए गए।

हैजा का वायरस मिलने के बाद दोगुना क्लोरिनेशन के निर्देश

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के आसपास और बार्डर वाले क्षेत्रों के प्राकृतिक जल स्रोतों में विबरियू कोलरा वायरस (हैजा) मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित विभागों को जल स्रोतों को दोगुना क्लोरीनेट करने के निर्देश दिए हैं ताकि समय रहते जानलेवा बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके। यह वायरस इतना भयानक है कि मरीज को उल्टियां और दस्त लग जाते हैं।

इससे ग्रस्त मरीज को चार से पांच बार दस्त आने पर मरीज की मौत हो सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी मामला अस्पताल नहीं पहुंचा है। हालांकि वायरस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सहित कमेटी को सचेत रहने के निर्देश पहले ही दे दिए हैं। विभागीय कर्मचारियों ने लोगों को ओआरएस बांटना पहले ही शुरू कर दिया है। यह वायरस हैंड पंप, बावड़ियों सहित अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों में पाया गया था। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह के साथ स्रोतों को

दोगुना क्लोरिनेट करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बद्दी के आसपास के क्षेत्रों और बार्डर एरिया में प्राकृतिक जल स्रोतों में विबरियू कोलेरा नाम के वायरस से होने वाली बीमारी पर काबू पाने के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों को दोगुना क्लोरिनेट करने के निर्देश दिए हैं।

फूड लाइसेंस के बिना मांस बेचने वाले 25 कारोबारियों को नोटिस

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

खुले में मीट का व्यापार करने वाले लोगों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने 25 लोगों को बिना फूड लाइसेंस व स्वच्छता की सरेआम धज्जियां उड़ाने पर पकड़ा है। विभाग ने आगामी कार्रवाई करते हुए नोटिस भेजा है। भेजे गए नोटिस के हिसाब से 15 दिन में संतोषजनक जवाब न आने पर कोर्ट में केस को भेजा जाएगा। उक्त सभी लोग सड़कों के किनारे रेहड़ी फड़ी लगाकर और सड़क में जमीन पर बैठकर खुलेआम बिना ढके मीट बेचने का धंधा कर रहे थे। यही नहीं बिना फूड लाइसेंस व बिना बेसिक हाइजीन ज्ञान के मीट को बेचने में लगे थे। विभागीय टीम ने नालागढ़ व सोलन के बसाल में निरीक्षण के दौरान खुले, बिना ढके मीट का व्यापार करने वाले लोगों को पकड़ा है। लाइसेंस मांगें जाने पर कोई भी संबंधित दस्तावेज न होने पर विभाग ने नोटिस जारी किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि सोलन के बसाल और नालागढ़ में सड़कों के किनारे बैठकर खुले में मीट का व्यापार करने वाले 25 लोगों को पकड़ा है। जिसके पास फूड लाइसेंस भी नहीं था। वहीं स्वच्छता भी नहीं अपनाई जा रही थी। उनके औजारों में भी जंग लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग की ओर से 15 दिन का नोटिस जारी किया गया। है। नोटिस का संतोषजनक जवाब न आने पर कोर्ट में केस किया जाएगा।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

विकास कार्यों पर राशि खर्च न करने वाली पंचायतों को जारी होंगे नोटिस

द रीव टाइम्स, हमीरपुर

पंचायत समिति सुजानपुर की बैठक अध्यक्ष सपना कुमारी की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिप अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। खंड विकास अधिकारी कीर्ति चंदेल ने बताया कि अधिकतर पंचायतों में विकास कार्य के लिए दी गई धनराशि कार्यों पर खर्च नहीं हो पा रही है। इस कारण यह राशि वापस आ रही है। इस समस्या पर गहनता से विचार कर कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। बैठक में जिलाभर में बढ़ रहे नशे पर सुजानपुर पंचायत समिति ने गहरी चिंता जताई है। समिति ने नशे की रोकथाम के लिए व्यापक कदम उठाने का निर्णय लिया है। सुजानपुर विकास खंड के तहत सभी पंचायतों के सार्वजनिक स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाने का निर्णय लिया गया है। चेतावनी बोर्ड पर नशे की रोकथाम और नशा करने वालों पर चालान का प्रावधान अंकित होगा। बैठक में पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की रिपोर्ट, साथ ही पंचायत समिति के पेंडिंग कार्यों को भी आगामी पंचायत समिति बैठक तक पूरा करने के निर्देश दिए गए।

45 लाख से लंबलू में लगेगा ठोस कचरा संयंत्र

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

विकास खंड बमसन में प्लास्टिक को रि-साइकिल करने के लिए 45 लाख रुपये की लागत से लंबलू में ठोस कचरा संयंत्र स्थापित होगा। इसके लिए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विकास खंड बमसन संयंत्र स्थापित करने वाला जिले में पहला विकास खंड होगा। पंचायत समिति बमसन की बैठक पंचायत समिति सभागार टौणी देवी में अध्यक्ष सुभाष चंद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कई विभागों के अधिकारी और उनके प्रतिनिधि गैर हाजिर रहे। इसका समिति के सदस्यों ने कड़ा एतराज जताया है। समिति की बैठक में उपस्थित न होने वाले विभागीय अधिकारियों से जवाब तलब करने की मांग की गई। कई विभागों के अधिकारी जन समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। बैठक में पंचायत समिति के बनने वाले भवन पर चर्चा की गई तथा जल्द ही इसके लिए भूमि तय करने का निर्णय लिया गया। जिससे आगामी कार्रवाई शुरू की जा सके। पंचायत समिति इसे मैरिज पैलेस नहीं बल्कि समिति का भवन बनाएगी। मैरिज पैलेस को लेकर मात्र कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे है। इसके साथ ही बैठक में कई विकासात्मक कार्यों पर चर्चा की गई। जिससे आगामी दिनों में पंचायत के माध्यम से विकास की गति को बल मिल सके। समिति के सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने दिया। बैठक में मुद्दा उठाया गया कि टौणी देवी तहसील में चरित्र प्रमाण-पत्र के लिए पहले टौणी देवी आना पड़ता है तथा उसके बाद भोरंज, सुजानपुर व हमीरपुर थानों के चक्कर लगाने पड़ते है। पहले पंचायत प्रधान के वेरिफाई करने के बाद लोग सीधे थाने जाएं और वहां से वेरिफाई करवाकर तहसील आएं। जिससे उनका समय और धन दोनों की बचत हो सके। इसके लिए उपायुक्त हमीरपुर से उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग में जगह-जगह रिक्त पड़े पदों को भरने के साथ ही अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की गई।

स्मार्ट सिटी में खुले में कूड़ा फैंका तो भरना होगा जुर्माना

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

अब स्मार्ट सिटी धर्मशाला में खुले में कूड़ा फेंकने पर जेब ढीली करनी होगी। नगर निगम धर्मशाला ने दो अक्तूबर के बाद शहर में खुले में कूड़ा-कचरा फेंकने वालों पर सख्ती की मन बना लिया है। ऐसे लोगों पर 500 से लेकर पांच हजार रुपये तक जुर्माना भरना होगा।

नगर निगम धर्मशाला ने डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण एवं निष्पादन वाई-लॉ में सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने, खुले में शौच व पेशाब पर जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। खुले में शौच अथवा पेशाब करने पर 500 रुपये जुर्माना तथा इसके अलावा अलग-अलग श्रेणियों के संस्थानों पर खुले व सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फैलाने या फेंकने पर 500 से लेकर 5000 रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। एमसी ने लोगों से कूड़ा एकत्रित करने वाले वाहनों या अंडरग्राउंड कूडादानों में कूड़ा डालने का आग्रह किया है। अन्यथा नगर निगम दो अक्तूबर के बाद खुले में शौच या कूड़े के निष्पादन पर दोषियों पर जुर्माना लगाएगा। उधर, एमसी आयुक्त ने सभी लोगों विशेषकर गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट हाउस, शिक्षण संस्थानों व व्यापारियों से स्वच्छता से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता फैलाने का आह्वान भी किया।

बीडीसी की बैठक अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर लोगों में रोष

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

विकास खंड स्वारघाट की पंचायत समिति की त्रैमासिक बैठक बीडीसी चेयरमैन हिमा देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष बिलासपुर अमरजीत सिंह बंगा और विकास खंड अधिकारी स्वारघाट अनिल ककड़ विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में हर बार की तरह इस बार में बिजली बोर्ड, ट्रांसपोर्ट, आईसीटीएस, स्वास्थ्य विभाग से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। इस कारण इन विभागों के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। बैठक में स्वारघाट विकास खंड की पंचायतों के 11 बीडीसी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बीडीसी सदस्यों ने अपनी मांगों व समस्याओं को लेकर उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में लोकनिर्माण विभाग से संपर्क सड़कों की मरम्मत करने बारे और आईपीएच विभाग से पानी की समस्या व बरसात के समय टूटी और खराब पाइप लाइनों को बदलने की मांग की गई। बीडीओ स्वारघाट ने उपस्थित बीडीसी सदस्यों को स्वच्छता ही सेवा अभियान की जानकारी दी और इस अभियान में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया।

धर्मशाला में पहली बार उपचुनाव

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला में करीब तीन दशक बाद भाजपा का चेहरा बदलेगा, जबकि इस सीट पर पहली बार उपचुनाव होगा। हालांकि, साल 1985 और 1982 में प्रदेश में सरकार गिरने से दो बार मध्यावधि चुनाव हुए हैं। लेकिन, इस बार यह पहला मौका है, जब धर्मशाला विस क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से पांच बार जीत दर्ज कर किशन कपूर करीब दो दशकों तक विधानसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। विस क्षेत्र में कांग्रेस की बजाय भाजपा का ही अधिक दबदबा रहा है। अब तक 11 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पांच और भाजपा प्रत्याशी छह बार जीत दर्ज करवा चुके हैं जबकि एक बार जनता पार्टी भी धर्मशाला से जीती है। साल 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस को केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिला। देश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल को देखते हुए वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में विधानसभा भंग कर चुनाव करवा लिए थे। हालांकि, उस समय विधानसभा को ढाई साल बचे थे। विस चुनाव में कांग्रेस को 68 में से 58 सीटें मिली थीं। धर्मशाला से मूलराज पाधा कांग्रेस की सीट से जीते थे।

डीसी ने जांचा सड़क निर्माण कार्य, दिए उचित दिशा-निर्देश

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

उपायुक्त हरिकेश मीणा हाल ही में शहर में व्यवस्था का जायजा लेने पहुंच गए। उपायुक्त ने नादौन चौक से बस स्टैंड तक लोक निर्माण विभाग की ओर से किए जा रहे सड़क, नालियों तथा फुटपाथ के कार्य तथा सड़क के दोनों ओर राजस्व विभाग द्वारा की गई निशानदेही के कार्य का विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बिजली तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सड़क के दोनों तरफ बेतरतीब तरीके से लटके बिजली के तारों, खंभों तथा पेयजल पाइपों को हटाने के निर्देश दिए ताकि, शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को लोगों को पेयजल कनेक्शन सुव्यवस्थित तरीके से प्रदान करने को कहा। बस स्टैंड हमीरपुर के पास लोक निर्माण विभाग की साढ़े पांच कनाल भूमि पर डबल लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। साथ में पार्किंग के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को डिजाइन तैयार करने के निर्देश दिए तथा साथ ही एमसी को नोटिस भेजने के निर्देश दिए। खोखा धारकों को भी सही स्थान पर व्यवस्थित किया जाएगा। लेकिन, बस स्टैंड के पास खाली भूमि पर अलग तरीके से डबल वे सड़क का निर्माण किया जाएगा। स्थानीय पाठशाला के ग्राउंड की ओर जाने वाले रास्ते तथा गेट को भी भव्य एवं सुंदर ढंग से निर्मित किया जाएगा।

कठलग के उजड़े परिवारों की मदद करेगा केंद्र

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीते दिनों हमीरपुर में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों ने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि मकान के साथ उनकी कृषि योग्य भूमि भी लैंड स्लाइड की जद में आ गई है। खेतीबाड़ी व पशुपालन से गुजारा करने वाले लोगों के समक्ष जमीन न होने के कारण रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपदा से पीड़ित परिवारों के लिए मकान बनाने को प्रदेश सरकार शीघ्र ही जमीन मुहैया करवा देगी तथा इसके अलावा जो भी संभव होगा केंद्र से भी मदद की जाएगी। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सांत्वना दी तथा उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने घुमारवीं की कसारू पंचायत के कठलग (करयालग) गांव में बरपे कुदरत के कहर से हुई भारी लैंड स्लाइडिंग से बेघर हुए सात परिवार के सदस्यों से मिलने करयालग पहुंचे। जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवारों की समस्याओं को सुना तथा उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने लैंड स्लाइड वाले स्थल का भी जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री ने उपायुक्त बिलासपुर को लैंड स्लाइड वाले स्थल की जांच करवाने के आदेश दिए। सांसद ने स्थानीय लोगों से भी इसके बारे जानकारी ली। जबकि इससे पहले घुमारवीं में लोगों से संवाद करके उनकी समस्यों को सुना।

बिलासपुर में बनाए गए 43,752 गोल्डन कार्ड

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने कहा कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत अब तक जिले में 43 हजार 752 गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिले में डेंगू और अन्य जल जनित बीमारियों के बारे में लोगों को समय पर जागरूक और फॉगिंग करने का ही परिणाम है कि डेंगू और स्वाइन फ्लू तथा अन्य बीमारियों पर नियंत्रण है। उपायुक्त राजेश्वर गोयल प्रशासन में दक्षता लाने के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में निर्मित होने वाले भाषा एवं संस्कृति विभाग के इंडोर ऑडिटोरियम की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है जिसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा रहा है। उन्होंने डीआरओ को निर्देश दिए कि बिलासपुर में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए शीघ्र ही उपयुक्त भूमि का चयन करें। उन्होंने उपनिदेशक उच्च शिक्षा को भी निर्देश दिए कि वे केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं की सभी औपचारिकताएं भी शीघ्र पूर्ण करें। उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि जिला में मशरूम व हल्दी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक किसानों को शिविरों के माध्यम से जागरूक कर इसका उत्पादन करने के प्रेरित करें ताकि किसान इसकी खेती करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो सकें।

मशरूम के उत्पादन के लिए अब तक 8 प्रशिक्षण शिविरों में 320 किसानों को तथा 1 हजार किसानों को हल्दी उत्पादन के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस अवसर पर उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि 13 अक्तूबर को विधानसभा क्षेत्र झंडूता के कलोल में 15वां जनमंच आयोजित किया जाएगा। 9 पंचायतों का चयन किया गया है जिसमें ग्राम पंचायत कलोल, घराण, सनीहरा, कोसरियां, मलरांओं, पपलोआ, धनी, डूडीयां तथा कुल्ज्यार शामिल की गई हैं।

सैनिक स्कूल को प्रदेश सरकार ने बंद की ग्रांट

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

एनडीए की नर्सरी कहे जाने वाला प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल सुजानपुर आजकल आर्थिक तंगहाली से गुजर रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल के पास भवन मरम्मत तक करवाने के पैसे नहीं हैं। स्कूल प्रशासन ने उच्च अधिकारियों को स्कूल की खस्ताहाल के बारे में अवगत करवा दिया है। वर्तमान में स्थिति यह है कि राज्य सरकार से मिलने वाली ग्रांट भी स्कूल को नहीं मिल रही है। बच्चों को मिलने वाली रिफ्रेशमेंट ग्रांट को भी राज्य सरकार ने देना बंद कर दिया है। हालांकि इस समस्या को लेकर हाल ही में स्कूल का एक प्रतिनिधिमंडल उप प्रधानाचार्य की अगुवाई में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में मिला था। उन्हें समस्याओं के बारे में अवगत करवाया, लेकिन इसके बावजूद स्कूल को राज्य सरकार की ओर से कोई भी ग्रांट जारी नहीं की गई है। जिस स्थान पर स्कूल कैंपस चल रहा है उस भूमि को स्कूल प्रशासन अपने नाम आज तक नहीं करवा पाया है। स्कूल कैंपस में स्मार्ट क्लासरूम सुविधा भी बंद है, क्योंकि 11 स्मार्ट रूम खस्ताहाल होने के बाद अभी तक सही नहीं हो पाए हैं। 500 से ज्यादा छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल में स्थायी डॉक्टर की तैनाती नहीं हो पाई है। स्कूल के पास अपना कोई ग्राउंड नहीं है। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल को चारदीवारी तक उपलब्ध नहीं है। स्कूल वर्तमान में रिजर्व रखे गए फंड से चल रहा है, वह भी अब खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में राज्य सरकार अगर स्कूल के लिए फंड जारी नहीं करती है तो स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगा। भवन मेंटेनेंस के लिए करीब सवा करोड़ रुपये स्कूल प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग को दिए हैं, लेकिन पैसा जारी होने के बावजूद कार्य नहीं हो रहा है।

बिना लाइसेंस दवाई बेचने पर चिकित्सक को 3 साल की कैद

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

बिना लाइसेंस के एलोपैथी दवाइयां बेचना एक आयुर्वेदिक चिकित्सक को भारी पड़ा है। बिना लाइसेंस के दवाई बेचने पर उसे तीन साल की कैद और एक लाख का जुर्माना भरने की सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पहली मार्च, 2011 को ड्रग इंस्पेक्टर व पुलिस ने डमटाल स्थित एक आयुर्वेदिक क्लीनिक पर छापामारी की थी। इस दौरान मौके पर कई एलोपैथिक दवाइयां वहां पर टीम ने बरामद की थीं। इस पर जब ड्रग इंस्पेक्टर ने क्लीनिक संचालक से दवाइयां बेचने का लाइसेंस व आरएमपी का प्रमाण पत्र दिखाने को कहा, तो वह इसे प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके चलते एएसआई सर्वजीत सिंह, हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह, रमेश चंद, संगत राम व जीतराम की उपस्थिति में सभी दवाइयों को सील कर दिया गया। तीन मार्च, 2011 को चालान कोर्ट में पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह पेश किए गए। वहीं अदालत में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने चिकित्सक रवि महाजन को तीन साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने का सजा सुनाई।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

स्कूलों से निकलने वाला कूड़ा होगा रिसाइकिल

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

स्कूलों से निकलने वाला कचरा अब रिसाइकिल किया जाएगा। इससे होने वाली आमदनी को स्कूल के विकास में लगाया जाएगा। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि स्कूल में टॉफी, चाकलेट, बिस्कुट आदि कचरा निकलता है। इसे एक बोतल में भर कर रखें। ज्यादा मात्रा होने पर इसे स्कूल में जमा करवाएं। इसके बाद कमेटी के कर्मचारी एकत्र कर उसे रिसाईकिल के लिए भेजेंगे। इससे जो आय होगी उसे स्कूल के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। उन्होंने सभी पाठशालाओं के प्रधानाचार्यों से आग्रह किया कि वे पाठशालाओं में बाहर से आने वाले प्लास्टिक के कचरे को एक जगह एकत्रित करके उसे रिसाइकिल के लिए भेजें ताकि स्कूल प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ हो। इस अवसर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी की प्रधानाचार्य डॉ. प्रतिभा वैद्य, नगर परिषद मंडी के सचिव बीआर नेगी, मेरे अपने संस्था के संयोजक विनोद बहल, सह संयोजक अनिल शर्मा, सदस्य हेमंत शर्मा एवं ज्योत्स्ना टंडन, अजय कुमार के अतिरिक्त पाठशाला के अध्यापक और बच्चे उपस्थित रहे। गर्ल्स स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी शहर को देश के टॉप 100 स्वच्छ शहरों में लाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मंडी को जनवरी 2020 तक स्वच्छता इंडेक्स में पहले 100 शहरों में शामिल करवाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए जनभागीदारी जरूरी है। टॉप 100 में आने के लिए आवश्यक है कि शत-प्रतिशत कूड़ा एकत्र हो और घर पर ही सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग रखने की व्यवस्था को सौ फीसदी लागू किया जाए।

दुबई में हिमाचल की लोक संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे दीप धनंजय

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

राष्ट्रीय स्तर पर चित्रकारी में अपना नाम चमकाने के बाद कुल्लू के युवा चित्रकार दीप धनंजय अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुबई में होने जा रहे आर्ट कैंप और प्रदर्शनी में प्रतिभा दिखाएंगे।

दिल्ली स्थित अंतरराष्ट्रीय संस्था रेनबो आर्ट ग्रुप की ओर से लगाए जाने वाले कैंप में दुनिया भर के प्रसिद्ध चित्रकार हिस्सा लेंगे। भारत से 18 सदस्यों के दल में हिमाचल से धनंजय इकलौते चित्रकार हैं, जो इस कैंप में अपनी लोक संस्कृति से सराबोर पेंटिंग का प्रदर्शन करेंगे। धनंजय ने कहा कि प्रदर्शनी में अपनी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शृंगा ऋषि की चौहणी कोठी पर आधारित पेंटिंग के साथ देवी हिडिंबा, नग्गर का गौरी शंकर मंदिर, कुल्लू के पुरातन जीवन पर आधारित लोक संस्कृति, कुल्लू - मनाली की खूबसूरती पर आधारित चित्रों का प्रदर्शन करेंगे। वर्तमान में धनंजय भुंतर में अपनी चित्रकला अकादमी चला रहे हैं। इसमें वह बच्चों को चित्रकला की बारीकियां सिखा रहे हैं।

300 साल पुराना बड़ा देव विष्णु मतलोडा का मंदिर जलकर राख

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

हिमाचल के मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोमगाड़ के जुही में बड़ा देव विष्णु मतलोडा का 300 साल पुराना मंदिर जलकर राख हो गया है। काष्ठकुणी शैली में बने इस मंदिर में कुछ दिन पूर्व ही आग लगी।

कुछ ही पलों में ऐतिहासिक मंदिर पौराणिक मूर्तियों के साथ राख के ढेर में तबदील हो गया। इस अग्निकांड में 30 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर में देवता की सदियों से स्थापित पत्थर की मूर्तियां भी नष्ट हो गई हैं। मंदिर के भीतर देवता की अनेक कलाकृतियां बनाई गई थीं। मंदिर सोमगाड़ पंचायत के जूही गांव से दूर घने जंगल में स्थापित था। इस मंदिर का निर्माण बड़ा देव विष्णु मतलोडा के रथ से भी पहले किया गया था। इस मंदिर का अध्यात्मिक महत्व देव मतलोडा के चोहठ के बाद दूसरे सबसे प्रमुख मंदिरों में शुमार था। देवता के कामी धामी धर्मदास, इंद्र सिंह, डोला राम, वीर सिंह ने बताया कि मंदिर में देवता की बड़ी मूर्ति के अलावा पत्थर की कई छोटी अन्य मूर्तियां भी स्थापित थीं, जो नष्ट हो गईं।

पर्यटन नगरी मनाली से नौ बाल मजदूर रेस्क्यू

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

पर्यटन नगरी मनाली में नौ बाल मजदूरों को रेक्स्यू किया गया है। सभी बच्चे नेपाल और बिहार राज्य के बताए जा रहे हैं। मनाली पुलिस और श्रम विभाग की मदद से बच्चों पर काम करने वाली हिमालयन फ्रेंड्स ट्रस्ट की मदद से रेस्क्यू किया गया है। सभी बच्चों की उम्र 14 साल से नीचे है और उनसे मनाली में होटलों और दुकानों में काम करवाया जा रहा था। संस्था के निदेशक ब्रेस्त राम और को - ऑर्डिनेटर हंस राज ने कहा कि उनकी संस्था चाइल्ड लाइन के लिए काम करती है। हाल ही में उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से मनाली पुलिस और श्रम विभाग कुल्लू के साथ मिलकर नौ बाल मजदूरों को रेस्क्यू किया। सभी बच्चों को कुल्लू स्थित चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास पेश किया गया। जहां बच्चों को शेल्टर होम कलैहली तथा मनाली के शूरू स्थित दारूफजल में रखा गया है। अब सभी बच्चों का मेडिकल करवाया जाएगा।

इसके बाद उनकी पहचान की प्रक्रिया शुरू होगी। उधर, मनाली में बाल मजदूरी को लेकर दी दबिश से कुल्लू जिला में हड़कंप मच गया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने कहा कि पुलिस ने एक संस्था के साथ मनाली के नौ बाल मजदूरों को रेस्क्यू किया है।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में बॉलीवुड कलाकार मचाएंगे धमाल

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में सांस्कृतिक संध्याओं के लिए प्रशासन ने स्टार कलाकारों की सूची जारी कर दी है। पहली सांस्कृतिक संध्या पर 8 अक्तूबर को मशहूर गायक स्वरूप खान और नौ अक्तूबर को सुरेश वाडकर प्रस्तुति देंगे। 10 अक्तूबर को पंजाबी नाइट होगी। 11 को ज्योतिका टांगरी व कुशल पाल प्रस्तुति देंगे।

12 अक्तूबर को एनिमेटेड लेजर लाइट और साउंड शो होगा। 13 अक्तूबर को बॉलीवुड नाइट में पार्श्व गायक सोनू निगम अपनी मधुर अवाज का जादू बिखेरेंगे। 14 अक्तूबर को पहाड़ी नाइट होगी। उत्सव में सुरक्षा की दृष्टि से इस बार 106 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन सीसीटीवी कैमरों से दशहरा उत्सव की हर गतिविधि पर नजर रहेगी। पहले पुलिस ने 90 सीसीटीवी लगाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन दशहरा में किसी प्रकार की चूक न हो। इसके लिए अब 106 सीसीटीवी लगाने का निर्णय लिया गया है।

दशहरा उत्सव में इस बार 1700 पुलिस जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। ये दशहरा उत्सव के दौरान कलाकेंद्र, मेला मैदान, ट्रैफिक से लेकर देवी - देवताओं की सुरक्षा का काम देखेंगे। पिछले दशहरा के मुकाबले इस बार 200 अधिक जवान ड्यूटी पर लगाए जा रहे हैं। दशहरा की तैयारियों में पुलिस जुट गई है। दशहरा के लिए पुलिस ने ढालपुर को 11 जोन में बांटा हुआ है। अलग - अलग जोन में जवानों की ड्यूटी पहले से तय होगी। किसी के पास देवी-देवताओं की सुरक्षा का जिम्मा होगा तो किसी के पास कलाकेंद्र में सुरक्षा व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी होगी। गौर रहे कि दशहरा उत्सव में इस बार जिला भर के 331 देवी-देवताओं को निमंत्रण दिया गया है।

मनाली में बनेगी विश्व की दूसरी सबसे ऊंचाई वाली बंजी जंपिंग साइट

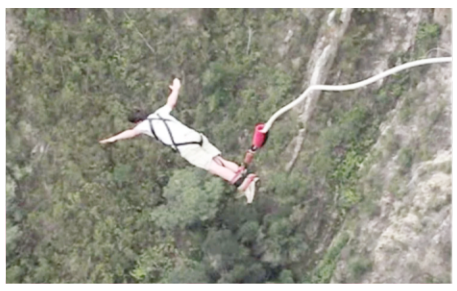

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

विश्वविख्यात पर्यटन नगरी मनाली में एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रेमी बंजी जंपिंग का लुत्फ भी उठा सकेंगे। मनाली में विश्व की दूसरी सबसे ऊंचाई वाली बंजी जंपिंग के निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंधित खेल संस्थान का प्रस्ताव सिरे चढ़ गया तो हिमाचल की दिलकश वादियों में भी हवा में छलांग लगाने का सपना पूरा हो सकेगा। मनाली में 186 मीटर की ऊंचाई से शरीर में रस्सी बांध हवा में छलांग लगाने के लिए बंजी जंपिंग का निर्माण करने की योजना है। अभी विश्व की दूसरी सबसे ऊंचाई वाली बंजी जंपिंग नेपाल के पोखरा में है। यहां की ऊंचाई 160 मीटर है। मकाओ में विश्व की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग 233 मीटर की है। साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रहे हिमाचल के मनाली में बंजी जंपिंग शुरू होते ही सैलानियों को बड़ा तोहफा मिल जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंधित खेल संस्थान मनाली के निदेशक कर्नल नीरज राणा ने मनाली में बंजी जंपिंग के लिए साइट तलाश ली है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी पॉजिटिव रही है। साइट निर्माण वन क्षेत्र में होना है। ऐसे में एफसीए की क्लीयरेंस के लिए प्रदेश सरकार को मजबूती से अपना पक्ष रखना होगा।

मनाली से विधायक और खेल मंत्री गोविंद के मुताबिक अभी इस दिशा में विचार चल रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि जुड़ जाएगी। उन्होंने बताया कि बीते दिनों ही मनाली में स्काई साइकिलिंग और जिप लाइन ट्रैक का सफल ट्रायल किया गया है। बंजी जंपिंग एक ऐसी गतिविधि है, जिसमें एक ऊंची जगह से एक बड़ी लोचदार रस्सी के साथ जुड़े रहते हुए कूदना होता है। यह ऊंचाई वाला स्थान आम तौर पर एक इमारत, पुल या एक क्रेन जैसी स्थायी वस्तु हो सकती है।

सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने के लिए बच्चों की मुहिम तेज

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

कुम्हारका स्कूल में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने के लिए बच्चों ने विशेष अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिला प्रशासन की ओर से इस दिशा में जारी निर्देशों पर अमल करते हुए स्कूल प्रशासन ने यह कदम उठाया है। शिक्षकों के आह्वान पर बच्चों ने महज एक दिन में तीन दर्जन से भी ज्यादा बोतलें सिंगल यूज प्लास्टिक सहित एकत्रित की है। सरकार के अभियान को लेकर शिक्षकों सहित बच्चों में खासा जोश है। स्कूल के कार्यकारी प्रभारी देवेंद्र दियोड़ ने बताया कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण, दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गया है। ऐसे में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकना चुनौतीपूर्ण है। सभी के सहयोग से ही यह मुमकिन हो सकता है। लिहाजा, सरकार और प्रशासन के निर्देशानुसार स्कूल शिक्षक और बच्चे सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने की दिशा में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की मुहिम से स्कूल स्टाफ और बच्चे लगातार जुड़े रहेंगे। इससे वातावरण को साफ और स्वच्छ बनाया जा सके। इकट्ठा किया गया सिंगल यूज बोतल बंद प्लास्टिक जिला प्रशासन के निर्देशानुसार रिसाइक्लिंग के लिए भिजवाया जाएगा।

चावल का विकल्प बनेगा ये प्राचीन अनाज, कैंसर-दिल के रोगों से बचाएगा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

औषधीय गुणों से भरपूर हिमाचल में घास प्रजाति का फॉक्सटेल मिल्लेट (काउणी) अब चावल का विकल्प बन सकेगा। यह बासमती चावल से भी महंगा होगा। चावल के रूप में इसके इस्तेमाल से किसी तरह की बीमारी का भय नहीं होगा। किसी भी उम्र में इसके सेवन से न केवल आप तंदुरुस्त रहेंगे, बल्कि इसमें पाए जाने वाले माइक्रो न्यूट्रेंट कैंसर, अस्थमा और दिल के रोगों से लड़ने में कारगर होंगे। कृषि विभाग ने परंपरागत कृषि योजना के तहत प्राचीन काउणी की व्यावसायिक खेती के लिए सफल ट्रायल कृषि विज्ञान केंद्र बजौरा में किया है। केंद्र ने तीन माह में व्यावसायिक दृष्टि से इसकी पैदावार तैयार कर दी है। विभाग प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। उसके बाद ही इसकी व्यावसायिक खेती के लिए नीति निर्धारित होगी। पहले चंबा, कुल्लू, किन्नौर की पर्वतीय श्रृंखला में इसकी बहुत खेती होती थी। डॉ. चंद्रकांता वत्स (पोषण विज्ञान विशेषज्ञ) ने बताया कि फॉक्सटेल मिल्लेट को स्थानीय भाषा में काउणी कहा जाता है। शोध में पाया कि इसमें कई पोषक तत्व हैं, जो माइक्रो न्यूट्रीएंटस में आते हैं। इनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस, फाइबर (रेशा), विटामिन बी और एंटी ऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं।

यह मैग्नीशियम और पोटाशियम का एक अच्छा स्रोत है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर दिल की बीमारियों से बचाता है। इसमें फाइबर अधिक होता है जो पाचन क्रिया को ठीक रखकर हाजमा दुरुस्त रखता है। साथ ही गैस, कब्ज और एसीडिटी से बचाता है। एंटी ऑक्सीडेंट शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है।

यह जानलेवा कैंसर की रोकथाम भी करता है। केवीके बजौरा के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. केसी शर्मा ने बताया कि परंपरागत कृषि योजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रायल पर आधारित फसल लहलहा रही है।

कूड़ा संयंत्र आरंभ करने से गुस्साएं ग्रामीणों ने जड़ा गेट पर ताला

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

कुरांह में कूड़ा-कर्कट फेंकने पहुंची चंबा नगर परिषद की गाड़ी को ग्रामीणों के विरोध के चलते वापस लौटना पड़ा। कूड़ा कर्कट फेंकने का विरोध कर रहे पांच पंचायतों के प्रतिनिधि, महिलाएं और पुरुषों ने जिला प्रशासन और नप चंबा के विरोध में नारेबाजी करते हुए कुरांह स्थित कूड़ा संयंत्र पर ताला जड़ दिया। ग्रामीण कुरांह में कूड़ा संयंत्र केंद्र न खोलने की मांग पर अड़े हुए हैं। गौरतलब है कि शहर से निकलने वाले टनों के हिसाब से कूड़े-कर्कट के निष्पादन के लिए कुरांह में स्थित कूड़ा संयंत्र केंद्र को दोबारा नप चंबा क्रियान्वित करना चाह रही है। इसी के चलते जब चंबा की कूड़े-कर्कट से भरी गाड़ी कुरांह स्थित संयंत्र पर पहुंची तो पंचायत प्रतिनिधि, ग्रामीणों, महिलाओं समेत वहां पर पहुंच गए।

ग्रामीण कुरांह में कूड़ा संयंत्र केंद्र को आरंभ करने से लोगों के स्वास्थ्य पर इसके विपरीत असर पड़ने की बात कह रहे हैं। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए मौके पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी पहुंची लेकिन, ग्रामीण कूड़ा-कर्कट केंद्र को न खोलने की मांग करते हुए इसे बंद करने की मांग पर अड़े रहे। ग्राम पंचायत बंदला के प्रधान अक्षय, मैहला उपप्रधान मनोज जसरोटिया, बंदला उपप्रधान छांगू राम, दाडुई के पूर्व प्रधान किशन चंद, मैहला पूर्व प्रधान उमेश, चड़ी पंचायत प्रधान दौलत राम, बालक राम, टिंकू सोनी ने बताया कि कुरांह स्थित कूड़ा संयंत्र के आरंभ होने से चड़ी, बंदला, गागला, मैहला, दाडुई पंचायतों की आबादी 20 हजार प्रभावित होगी। कहा कि कूड़ा संयंत्र से निकलने वाली विषैली गैस लोगों के स्वास्थ्य के साथ-साथ हमारी धरोहर रावी को भी दूषित करेगी।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

क्रेडिट सूचना कंपनियों (विनियमन) अधिनियम, 2005

इस अधिनियम को क्रेडिट सूचना कंपनियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 कहा जा सकता है।

यह पुरे भारत में लागु करने के लिए बनाया गया है।

पंजीकरण के लिए आवेदन

नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है

(1) क्रेडिट जानकारी का व्यवसाय शुरू करने का इरादा रखता है जो हर कंपनी इस तरह के रूप में रिजर्व बैंक के लिए पंजीकरण और तरीके के लिए एक आवेदन करेगा।

(2) हर ऋण सूचना कंपनी, इस अधिनियम के प्रारंभ पर

अस्तित्व में, ऐसे प्रारंभ से छह महीने की समाप्ति से पहले, इस अधिनियम के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक को लिखित में आवेदन करना होगा।

यह एक प्रमाण पत्र के लिए दी गई है जब तक इस अधिनियम के प्रारंभ पर अस्तित्व में एक ऋण सूचना कंपनी के मामले में, खंड 3 में कुछ भी नहीं है, एक ऋण सूचना कंपनी के कारोबार पर ले जाने से इस तरह के ऋण सूचना कंपनी को प्रतिबंधित करने के लिए समझा जाएगा बशर्ते कि पंजीकरण या पंजीकरण प्रमाणपत्र इसे करने के लिए नहीं दी जा सकती है कि रिजर्व बैंक द्वारा सूचित लिखित में सूचना के द्वारा होता है।

पंजीकरण का प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए रिजर्व बैंक की शक्ति

रिजर्व बैंक उप-धारा के तहत एक ऋण सूचना कंपनी को दी गई पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकते हैं

धारा 5 की अगर ऐसी कंपनी क्रेडिट जानकारी के व्यापार पर ले जाने के लिए रहता है या पंजीकरण का प्रमाण पत्र यह करने के लिए प्रदान किया गया है विषय, जो करने के लिए शर्तों में से किसी के साथ पालन करने में विफल रहा है या किसी भी समय (ग) उप - धारा (1) या उपधारा (2) धारा 5 के उप खंड (क) में निर्दिष्ट शर्तों के किसी भी पूरा करने के लिए विफल रहता है

रिजर्व बैंक के आदेश के खिलाफ अपील

धारा 5 या धारा 6 के तहत पंजीकरण के प्रमाण पत्र को रद्द करने के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक आवेदन की अस्वीकृति के आदेश से व्यथित एक क्रेडिट जानकारी कंपनी, केन्द्र सरकार के लिए एक अपील या किसी अन्य प्राधिकारी या न्यायाधिकरण पसंद कर सकते हैं जो अस्वीकृति या रद्द करने की इस तरह के आदेश, जैसा भी मामला हो, ऋण सूचना कंपनी को नहीं भेजी है जिस तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा नामित किया जा सकता है।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी, 94180 25649

आपका स्वास्थ्य हमारा परामर्श

अस्थि रोग (Diseases of Bone)

अस्थि रोग, मानव हड्डियों को प्रभावित करने वाली कोई भी बीमारी या चोट होती है। अस्थि रोग या हड्डियों के रोग और चोटें मानव कंकाल प्रणाली के असामान्यताओं के प्रमुख कारण हैं। हालांकि शारीरिक चोट, फ्रैक्चर का कारण बनती है, यह चोट बीमारी का रूप ले लेती है और इंसान पर हावी हो जाती है। फ्रैक्चर हड्डियों की बीमारी के कई सामान्य कारणों में से एक है।

ओस्टियोमलेशिया एवं रिकेट्स (Osteomalacia and Rickets)

क्या आप जानते है कि एक व्यस्क व्यक्ति को प्रतिदिन एक ग्राम कैल्शियम तथा 400–800 IU विटामिन-डी की जरुरत होती है। अस्थि के कैल्सीफिकेशन के लिए विटामिन-D की आवश्यकता होती है जो आंत से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। वयस्कों में कैल्शियम तथा विटामिन-D की कमी से, विशेषकर स्त्रियों में अस्थिम्रदुता (Osteomalacia) नामक रोग हो जाता है। जबकि बच्चों में इसके अभाव के कारण सूखा रोग (Rickets) हो जाता है।

ओस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis)

'आस्टियो' का अर्थ होता है 'अस्थि' तथा 'पोरस' का 'मुलायम' या 'छिद्रयुक्त'। 'ओस्टियोपोरोसिस' अस्थि ढांचे का ऐसा रोग है जिसमें अस्थि सघनता के कम होने एवं अस्थिमज्जा की संरचना के ह्रास से हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं तथा उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है।

सन्धिशोथ या गठिया (Arthritis)

एक अथवा अनेक सन्धियों का शोथ सन्धि-शोथ (Arthritis) कहलाता है। यह किसी भी आयु के व्यक्ति में पाया जा सकता है। परन्तु सामान्यतः प्रौढ़ तथा वृद्ध व्यक्तियों में अधिक होता है। यह दो प्रकार का होता है: ऑस्टियो और रयूमेटायड अर्थराइटिस। रयूमेटायड अर्थराइटिस एक प्रकार का polyarthritis है जो bilateral तथा सममित (Symmetrical) होता है। सर्वप्रथम यह शोध हाथ व अंगुलियों की लघु संधियों को प्रभावित करता है।

4. वैस्कुलर निक्रोसिस

सामान्यतः बुढ़ापा आने का प्रारंभ जोड़ों के दर्द से ही होता है। यह एक ऐसी ही बिमारी है, जो जोड़ो में तीखे दर्द के कारण रोगी को एक तरह से अपाहिज ही बना देती है। यदि इस रोग की चिकित्सा अच्छी तरह से नहीं की गई, तो यह कुल्हे के अर्थराइटिस में परिवर्तित हो जाता है। फलतः रोगी का चलना-फिरना अत्यंत कठिन हो जाता है।

इस रोग का अंतिम इलाज जोड़ो के बदलाव के लिए की जाने वाली शल्य-चिकित्सा को ही माना जाता है। इससे कुल्हे को लाइलाज स्थिति तक पहुँचने से बचाने में सफलता मिल जाती है।

अस्थि रोग के बारे में पता चलता है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें

डॉ0 के आर शांडिल
द रीव क्लिनिक, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें:hem.raj@iirdshimla.org

शिक्षक के रुप में करियर बनाऐं

भारत व अन्य देशों में समाज निर्माण के लिए शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक एक सभ्य समाज के निर्माण में मजबूत स्तंभ होते हैं। हमारे यहां शिक्षक होना गर्व की बात होती है, इसलिए कई माता-पिता अपने बच्चों को बड़े होने पर शिक्षक बनने की सलाह देते हैं। एक शिक्षक के रूप में करियर बनाने पर आप मान-सम्मान और अच्छी तनख्वाह पाकर अपना जीवन-यापन कर सकते हैं। समाज को अच्छे शिक्षकों की हमेशा जरूरत होती है। एक शिक्षक का विद्यार्थी के जीवन में, उनके माता-पिता की नजरों में अलग ही ओहदा होता है।

एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी के जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल देता है। शिक्षक होना अपने आप में कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता के साथ ही व्यक्तिगत योग्यता होना भी अनिवार्य है। यदि आपको शिक्षक बनने में रुचि है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह चयन करना होगा कि आपका रुझान किस उम्र के विद्यार्थियों को पढ़ाने में है। विद्यार्थियों की उम्र के हिसाब से आपकी शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता भी अलग-अलग होगी।

पहले आप सुनिश्चित कर लें कि आप प्ले स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, कॉलेजों व विश्वविद्यालय या अन्य किस शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाना चाहते हैं। इन सभी में शिक्षक के रूप में पद पाने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता कुछ इस प्रकार होनी चाहिए:

- प्री स्कूल के टीचर बनने के लिए आपको 'नर्सरी टीचर ट्रेनिंग' यानी कि NTT में एक साल का प्रमाणपत्र या डिप्लोमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है।
- नर्सरी या किंडरगार्टन में टीचर बनने के लिए आपको मोंटेसरी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बाद आप इन स्कूलों में टीचर बन सकते हैं।
- प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षक बनने के लिए आपको केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि CTET पास करनी होगी। आप शिक्षा-स्नातक यानी कि B-Ed की डिग्री भी ले सकते हैं। अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए आप आगे और भी पढ़ते हुए शिक्षा में परास्नातक (एमएड) M-Ed भी कर सकते हैं। इसे करना आपकी पद उन्नति के लिए लाभदायक होगा।
- यदि आपको योगा, खेल व शारीरिक फिटनेस का ट्रेनर बनना हैं, तब आपके लिए इसी विषय में ज्ञान व डिग्री लेनी अनिवार्य है।
- कॉलेज व विश्वविद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए आपके पास पसंदीदा विषय में विशेषज्ञता डिग्री होनी चाहिए। आप आगे M-Phil व Ph-D भी कर सकते है। आपकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ही यहां पर आपको पद मिलेगा।
- यदि आप UGC द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली NET परीक्षा पास कर लेते हैं, तब भी आप लेक्चरर व कॉलेज के अध्यापक बन सकते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप विभिन्न कॉलेजों में भर्ती के लिए आवेदन दे सकते हैं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

Future of Investors' Meet in Himachal

Around two and half decades of the globalisation of the economy, new doors were opened for entrepreneurs and industries to expand to any limit within their capacities. With the ever-increasing demand for essential commodities and services, the governments are slowly becoming liberal to allure industries towards the investment in their territories and assuring to provide the 'Ease of Doing Business' environment. All such initiatives are welcomed, provided the selection of the industries or the business enterprises are aligned with the ecological balance. Especially in the Himalayan region, due care is needed while opting the projects that impact vegetation and stability of young and fragile mountains.

The projects like cement production need not be encouraged in the hilly regions due to their contribution to air pollution and the associated ill-effects. And in the construction industry, the most essential projects need to be considered provided high-end technology is used to minimise the ecological misbalancing impact.

The second factor is to create an enabling environment for the industry to grow and flourish. Besides all political assurances, the long procedures and red-tapism at multiple levels prevent the creation of the enabling environment. The deep-rooted customary morality at multiple level reduces the enthusiasm of the investors to come forward because an entrepreneur thinks differently based on one's hard work and calculated risk where time management becomes crucial while dealing with the government system.

There are a dozen of Laws and Acts enough for creating confusion for any aspiring entrepreneurs. However, Modi Government 2.0 has significantly slashed more than 1,500 such redundant laws during Modi Government 1.0 regime but much is yet to be done. The government authorities sometimes seem having least to do with the implementation of the regulations but making people move around them remains the tendency. The attitude of the authorities is not educative and supportive, rather it is fault finding and punitive. In such scenario, how can one expect to create the enabling environment for the industries to grow and flourish?

There is a live example of the Department of Labour Welfare, Himachal Pradesh; once a Labor Inspector visited an organisation, he had just a cup of tea, discussed and appreciated the activities of the organisation and left the office. He never intended to examine the routine record available in any office. The next week the organisation received a long letter on failure to produce documents and non-compliance of various Acts and Rules. Some Acts were referred which were not even applicable to that organisation as there will perhaps be the standard proforma with the department which used to be issued to an entrepreneur or industry with all required documents frequently. The organization wrote an appropriate explanation without quoting that the said Labor Inspector never asked to produce all such documents as mentioned in the letter.

The matter was almost closed and the organisation never received reference of that letter again.

The organisation received thrice the similar fresh letters from the same office again

and every time the organisation kept on submitting the required documents. One such letter received one day before the due date and the compilation of the documents required latest data which would have needed a considerable amount of time and the organisation requested for next date of hearing which was not granted and the matter was subjected to the court where it got settled.

Even after this, the organization received matching communication twice and in reply a stereotypical message being passed along with documents every time. And this process seems ongoing causelessly, without fulfilling any purpose except the wastage of time and energy at both ends. When it was enquired from some enterprises in industrial areas, the intention and practices of the department came to know. As per the data of 2014-15, out of total 28521 inspections carried out by the Department of Labour and Employment Himachal Pradesh, challans of 2723 cases were lodged in the court.

Here the question arises, is the department seriously keen on seeing that the people working in different industries are not deprived of the justice, safety and growth? And is the department serious on implementing various regulations as mandated?

If so, the approach of the department could have of extending knowledge, information and support wherever lacking. And appreciate the enterprises' contribution to society and the nation. But in reality, it does not look like, except fulfilling the motives other than this. No conduction of such event has been reported so far on educating the industries and enterprises on labour laws. There are some redundant rules which need revision, like when going for recruitment, the industry needs to notify to the concerned employment exchange manually, which is merely an exercise to increase paperwork. Hardly any industry gets candidates purely through employment exchange as these exchanges have become mere white elephant with conventional work style.

A number of digitally rich, private job portals are working better than any employment exchanges which are still struggling in getting bundles of papers that simply occupy space in the offices and a burden on the environment. There is need to review the Acts, Rules and Procedures of various regulations to stop the "Inspector Raj" with which one can have first-hand experienced while getting the drug licenses for opening Medicine outlets in the state.

Until the government takes the due cognizance of all such irritants, the industry cannot flourish. The procedures and the processes need to be simplified with timeline stipulation.

Such procedures are becoming hurdles to the government itself. Many of the ambitious developmental projects of the government keep lingering on for decades and by the time these projects get reviewed again, their cost gets multiplied. As per data of MoEFCC, there are total 393 projects pending for various approvals out of which 151 projects are pending since 2015.

Government also struggling to set up Central University

The same is happening with the sole Central University in Himachal Pradesh which started functioning in 2010. The Centre has already released grants to all other new universities for infra development, except that of Himachal Pradesh. If the government itself is struggling for years to set up the university with central support, whatever be the reasons, how can we expect the industry to come forward after mobilising resources from banks on higher rate of interest and struggle for years to convert the business thoughts into actions? Many may come for a trial and gradually shift their focus as the same is happening in the existing industrial areas of Himachal.

Until, we value timeline and express sincerity for creating enabling environment by overcoming the related hurdles, our end goals will remain unfulfilled.

With the present industrial meet, the Himachal government seems quite serious and the recent initiatives on digitising permission process under section 118 is a welcoming step in this direction and hopefully the rest will follow. Apart from the priority sectors of health and education in Himachal Pradesh, the investors need to encourage for venturing into a) **Surface Transport** including Sleeper Buses, more Deluxe and AC Buses, City Trams, Mono Rails, Flyovers, Ropeways, etc.; b) **Air Transport** including creating more Small Airports, Helipads, operating Heli Taxis, Small Airbuses and Air Ambulances etc. The air services are in pathetic conditions and the UDAAN scheme launched by the Ministry of Civil Aviation is a big failure in Himachal context. From Delhi to Shimla and vice versa, the average air ticket price is Rs. 18000 against the proposed Rs. 2200 or Rs. 3000 for one side defeating the very objective of the scheme of letting the common citizen of the country fly; c) **Natural and Organic Agro-Practices** including Production of Safe Fruits, Vegetable, Traditional Crops Production, Food Processing, Cold Storage, Commercial Agro-Forestry etc.; d) **Afforestation** including Eco-Tourism Based Sustainable Commercial Forestry, etc.; e) **Tourism** including Wellness and Village Tourism, Mountain Based Sports, Creation of Tourism Related Infrastructure, etc.; f) **Energy** including Solar and Wind Energy Plants, Bio-mass Energy Based Micro and Smaller Plants and g) **Others** including Software Industry, IT Parks, Data Analytics, Industries based on Water, Fresh Air, Clean Sunlight and Greeneries, etc.

Hopefully, the present meet will come out with some significant outcome which will determine the future of the Investors Meet.

Dr. L.C. Sharma
Editor in Chief
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

बच्चों के टूर्नामेंट हो रहे हैं सरकार की अनदेखी के शिकार

नाममात्र की सुविधाओं से क्या ऐसे निखरेगी खेल प्रतिभाऐं

महीनों अध्यापक रहते हैं स्कूल से गायब खेलकूद के नाम पर, पढ़ाई का भी नुकसान

वैश्विक स्तर पर आज भारत एक खेल शक्ति के रुप में उभर रहा है । हमने राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलों में तिरंगा फहराया है । इसमें ऐसी खेल प्रतिभाऐं हैं ही जो शहरी क्षेत्रों में खेल की समस्त सुविधाओं को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ी हैं लेकिन इसमें ऐसे भी खिलाड़ी शामिल है जो गांव की मिट्टी और धूलधूसरित संघर्ष का तिलक कर भारत का नाम रोशन करने में पीछे नहीं है। हिमा दास, स्वप्ना आदि खिलाड़ियों को कैसे भूल सकते हैं जिनके माता- पिता ने न जाने कितने संघर्ष के बाद और ग़रीबी में अपनी इन प्रतिभाशाली बच्चियों को इस मुकाम तक पहुंचाया होगा । ऐसी न जाने और कितनी ही प्रतिभाऐं हैं जिन्होनें ग़रीबी से उठकर अपनी प्रतिभा के दम पर देश का नाम रोशन किया ।

यहां हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कहने के लिए क़लम उठी तो यह देखकर बड़ा अफसोस होता है कि हिमाचल में ग्रामीण खेलकूद के लिए औपचारिकताओं का ही सहारा लिया जा रहा है ।

स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता महज़ औपचारिकता

हिमाचल के स्कूलों में ब्लॉक स्तर, ज़िला स्तर और फिर राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताऐं आयोजित की जाती है । इनमें स्कूलों से प्रतिभाऐं चुनकर आती हैं । वास्तविकता ये है कि अधिकतर स्कूलों में विद्यार्थियों को न तो सही प्रकार से कोचिंग दी जाती है और न ही इसके लिए खर्च ही पर्याप्त है। क्या इस प्रकार निखरेगी ग्रामीण प्रतिभाऐं ? सच तो ये है कि हमें मंथन करने की आवश्यकता है कि ये टूर्नामेंट होने भी चाहिए कि नहीं ? क्योंकि अध्यापकों की इसमें जाने के लिए लगी होड़ और अपने स्कूल में पढ़ाई को बाधित कर क्या कोई इस प्रकार बाकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा सकता है ? इसमें अध्यापकों की यूनियन की भूमिका भी अधिक रहती है जिससे ये खेल अध्यापकों को अपनी कक्षाओं से दूर कर रहे हैं। इन खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए सरकार का बजट भी कम हैं तथा इसके लिए कई ब्लॉक में तो सभी अध्यापकों 500/ या 1000/ रुपये एकत्रित किए जाते हैं और उस पर इन खेलकूद प्रतियोगिताओं में अध्यापकों का जमवाड़ा वहां लग जाता है । इनमें कुछ अध्यापक तो पूरा वर्ष इन्हीं टूर्नामेंट्स की प्रतीक्षा में रहते हैं तथा किसी भी कीमत पर उन्हें इसमें शामिल होने के आदेश चाहिए होते हैं । यानि उनके स्कूल में बच्चों की पढ़ाई चाहे बाधित होती रहे, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता । उनको बस टूर्नामेंट में जाना है । इन खेलकूद प्रतियोगिताओं में अध्यापकों का जमवाड़ा लग जाता है और स्कूलों में प्रतिनियुक्ति के लिए अध्यापकों की उठक-बैठक भी शुरु हो जाती है। ये खेलकूद प्रतियोगिताऐं महज़ औपचारिकताऐं बन कर रह गई है ।

सरकार की प्राथमिकता में बच्चों की पढ़ाई या खेलकूद

स्कूलों में महीनों तक चलने वाले खेलकूद प्रतियोगिताओं में अध्यापकों के शामिल होने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। लेकिन इन प्रतियोगिताओं में अध्यापक अपनी ड्यूटी लगाने के लिए सिफारिशें लगाते हैं । ऐसा क्या है इन खेलकूद प्रतियोगिताओं में कि कुछ अध्यापक अपनी कक्षाओं को छोड़कर इसमें शामिल होना ही चाहते हैं । शायद सरकार मूक बन कर देख तो रही है लेकिन उस पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझती । क्या शिक्षा विभाग को नहीं पता कि एक टूर्नामेंट में कितने शिक्षक भाग ले रहे हैं और उनके कारण कितनी ही कक्षाऐं और स्कूली बच्चे प्रभावित हो रहे हैं ? इन उच्चाधिकारियों को सारे तथ्य पता है लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया और कार्यवाही नहीं की जाती । कई ऐसे भी स्कूल हैं जहां किसी दूसरे स्कूल से प्रतिनियुक्ति पर अध्यापक को भेजने में भी दिक्कत आ जाती है क्योंकि अधिकतर स्कूलों से इन टूर्नामेंटस् में अध्यापक भागे होते हैं । क्या सरकार की प्राथमिकता खेलकूद है या बच्चों की पढ़ाई ? इस पर मंथन होना ही चाहिए । इन खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए जो कोचिंग कैंप लगते हैं उसमें भी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है । जब आम अभिभावकों से बात की जाती है तो वो अक्सर इसकी शिक़ायत करते हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है ।

यूनियन के मायने क्या है

एक शिक्षक कां सबसे बड़ा धर्म बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना है, उसे बेहतरीन शिक्षा देना है । उस शिक्षक की रोजी-रोटी और परिवार की सुख-सुविधाओं का आधार है ये बच्चें जिनके कारण ही इनको ये सब प्राप्त हो रहा है । ऐसे में शिक्षा में शिक्षक को अपने नैतिक मुल्यों के साथ गुरु की भूमिका में रहने की आवश्यकता है । आज प्रदेश में शिक्षक यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए तो लड़ रहे हैं लेकिन उन बच्चों की बात कोई नहीं करता जिनके कारण उनका परिवार रोटी खा रहा है । यूनियन के लोग हैं तो शिक्षक, लेकिन पूरा प्रदेश का भ्रमण करने की शक्तियां वर्ष भर लेकर घूमते हैं। संगठन होना अति आवश्यक है लेकिन उसकी सार्थकता तभी है जब उसका उपयोग वाज़िब तौर पर और सही समय पर हो । एक शिक्षक के लिए क्या ये उचित है कि वो राजनीति करते हुए अपनी तनख़्वाह किसी स्कूल से लें जहां उसका आना-जाना कभी-कभार ही होता है? वर्ष भर ये नेता अध्यापक यूनियन का नाम लेकर घूमते हैं । उनकी भागीदारी ही इन टूर्नामेंटस् में सबसे अधिक होती है और अपनी पसंद के अध्यापकों की ड्यूटी भी लगाते हैं । ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनियन तक ही सीमित है, राजनैतिक संबन्धों को भी सार्वजनिक रुप से देखा जा सकता है । अक्सर सरकार के मुखिया या मंत्री भी इस बात को अनचाहे ही सही कह ही देते हैं कि अध्यापक अपनी ड्यूटी से मतलब रखें । राजनीति न करें । यूनियन अपने अधिकारों के लिए एक संबल के रुप में कार्य करती है लेकिन नैतिकता ये है कि इसके कारण कभी कर्तव्यों को नहीं भुलाया जा सकता है ।

पैसा नहीं तो बंद हो ये खेलकूद प्रतियोगिताएं

सरकार एक सीमित बजट और नाममात्र पैसों से बेहतरीन खेलकूद प्रतियोगिताऐं करवाने की योजना पर ही काम कर रही है । इस सीमित बजट में कोचिंग और टूर्नामेंट संभव नहीं हो पाते । इसके लिए अध्यापकों से पैसा एकत्रित किया जाता है । उसके बाद टूर्नामेंट में अध्यापकों की फौज खड़ी हो जाती है । बच्चों के साथ इसे न्याय नहीं कहा जा सकता । सरकार को एक उचित बजट का प्रावधान कर समस्त सुविधाऐं प्रतिभागी खिलाड़ी बच्चों को उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है । ताकि ग्रामीण स्कूलों से भी बेहतरीन खेल प्रतिभाऐं उभर कर सामने आ सके और बच्चों को इसमें भी भविष्य नज़र आऐ । लेकिन यदि इसी प्रकार टूर्नामेंट होते रहे तो स्कूलों में प्रभावित हो रही पढ़ाई के लिए किसे जिम्मेवार ठहराया जाऐगा ? न तो अध्यापकों की सूची ही क्रम में होती है और न ही प्रतिनियुक्ति के लिए क्रमवार व्यवस्था है । एक से दूसरे स्कूल में अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति करके खेलकूद के समय को जैसे-तैसे निकाला जाता रहा है । जबकि मूल कर्तव्य बच्चों की पढ़ाई का है जिसे प्रभावित नहीं किया जा सकता है । इसे समझने की आवश्यकता है सरकार को भी और इन युनियन के पदाधिकारियों को भी । युनियन में पदाधिकारी बनने का यह मायने कदापि नहीं है कि उन्हें बच्चों को कक्षा में पढ़ाने का अधिकार नहीं रहा है और वो युनियन की गतिविधियों में यहां-वहां के दौरे करते रहे । बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है । मौज-मस्ती के लिए यह सेवा नहीं मानी जा सकती है । यहां देश के भविष्य का निर्माण हो रहा है । यही पीढ़ी आने वाले समय में देश का भाग्य बनेगी । इस पीढ़ी को अधिक समय देना और तत्परता से उनकी शिक्षा में तल्लीन होकर सेवाऐं देना हर एक अध्यापक का कर्तव्य है ।

जनभागीदारी की आवश्यकता

मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इन खेलकूद प्रतियोगिताओं में ग्रामीण लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित बनाने में हम अमह भूमिका निभा सकते हैं । जब भी गांव में इस प्रकार के बच्चों के टुर्नामेंट्स होते हैं तो लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से अपना सहयोग देते हैं । ऐसे अनेक उदाहरण है जब स्थानीय पंचायतें, युवा मंडल, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय लोग अपना सहयोग देते हैं । ये अतिरिक्त प्रयास है जो स्कूल के लिए और बच्चों के लिए किए जा सकते हैं लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेवारी तय करनी होगी और एक समुचित बजट की व्यवस्था के साथ-साथ बच्चों के खान-पान, रहन-सहन के लिए उचित क़दम उठाने होंगे ।

सरकार उचित क़दम उठाए

जिन स्कूलों से अध्यापक टूर्नामेंट में सेवाऐं दे रहे हैं उन विद्यालयों को सरकार निरिक्षण करके यह सुनिश्चित करें कि बच्चों की पढ़ाई क्या सुचारु रुप से हो भी रही है अथवा नहीं ? और टूर्नामेंट में कितने अध्यापकों की वास्तविकता में आवश्यकता है और कितने वहां पर प्रतिनियुक्त किए गए हैं ? अध्यापकों के मौज-मस्ती के लिए इन टूर्नामेंट को संचालित नहीं किया जाता है बल्कि ग्रामीण विद्यालयों से खेल प्रतिभाओं को इसमें अवसर प्राप्त होता है जो आगे चल की इसमें अपने करियर को भी तलाश सकते हैं तथा देश का नाम रोशन कर सके । बच्चों की दी जाने वाली कोचिंग का भी निरिक्षण विभाग के उच्चाधिकारियों या सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा की जाए । साथ ही शिक्षक युनियन को भी अपने कर्तव्यों को समझने की आवश्यकता है । ऐसा न हो कि जिस कर्तव्य के निर्वहन हेतु सरकार इतना बड़ा बजट तनख़्वाह के रुप में खर्च करती है, उससे हटकर बच्चों का भविष्य ही दांव पर लग जाऐं। हमें अध्यापक नहीं, गुरु की परंपरा को अपनाते हुए नैतिक मुल्यों के ह्रास को बचाना है ।

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

MALALA'S REACTION OVER J&K NOT 'NOBEL'

The revocation of Article 370 in Jammu & Kashmir by the Indian government and the subsequent steps have attracted sharp reactions, both positive and negative, from within the nation and globally. Some people may be against the government's decision but as it appears, the majority of people have ubiquitously welcomed it. Being in the digital age, we get to see the reactions of people through their tweets, FB posts and any other platform that is available to the masses.

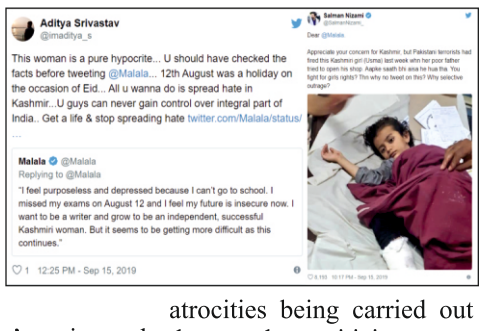

From the support of countless nations to Pakistan's crying and begging at the global platforms such as the United Nations has left them embarrassed. With the failure to gain support, Pakistan's keyboard warriors have gone overboard in peddling lies on the present situation in Kashmir. The stooges of Pakistan all over the world, and some within India, have been crying wolf consistently. One such irrelevant voice was of "Nobel Laureate" Malala Yousafzai, the Pakistani activist for women's education and the youngest Nobel Prize winner; she was awarded in 2014 at the age of 17 years.

Though it would not have been necessary to mention her nationality but her biased comments on the Kashmir issue invite critique of her true intentions. It cannot be denied that she is brave and despite facing the near-fatal attack on her by the Taliban, a story that is universally known, she has continued to remain active to propagate the female education in numerous ways at the international level. But her subsequent actions and statements against India and complete lack of condemnation for the atrocities being carried out on the minorities in Pakistan deserve sharp criticism.

In her tweets, Malala has again and again written about the "issues" faced by Kashmiris ever since the Article 370 has been revoked and urged the United Nations General Assembly (UNGA) to take cognizance of the matter. More recently, she tweeted about a young Kashmiri girl with whom she herself had a discussion and the alleged girl was worried about her future as she was not able to give her exam that was supposedly held on August 12; a lie which has been debunked as the said date was a holiday in India as it was the auspicious day of Eid. It was highly surprising and unfortunate for a person of Malala's stature to peddle such lies to further Pakistan's vicious agenda.

Several people pointed out Malala's fallacy and asked her if she was willing to criticise the Pakistani government and army's atrocities being carried on the minorities of her nation. Malala's response was either complete silence or the prompt blocking of the people who questioned her. Being a "Nobel Prize winner", Malala could have shown unbiased concern for humanity and shared few words condemnation. But unfortunately, it was too much to expect from her. One more thing that people usually point out is that despite her activism and her being fearlessly vocal about female education, she has not exhibited the same courage in returning to Pakistan to continue her activism or her education there; at present, she studies in Oxford University.

Her actions reek of hypocrisy, as on one hand she preaches about the importance of education for women and their empowerment, but she incessantly fails to address the issues prevailing in Pakistan that hamper the right to education for Pakistani women, specifically from the minority population who get abducted, raped, attacked...

The day Malala with sheer disinterest steps up to urge Pakistan to give equal rights to all its people, irrespective of their religion, that day will prove that she truly deserved being awarded the Nobel Peace Prize.

Shrava Gupta, Shimla (HP)
(Guest Writer)

लेखक के निजी विचार है, इसमें 'द रीव टाइम्स' की सहमति आवश्यक नहीं है

स्वास्थ्य सेवाओं में हिमाचल दिनों-दिन प्रगति कर रहा है ... डॉ. अजय कुमार गुप्ता

परिचय
डॉ० अजय कुमार गुप्ता
निदेशक
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

डॉ0 अजय कुमार गुप्ता मेडिसन विशेषज्ञ हैं। 1983 से सिरमौर के दूरपार क्षेत्र में सेवाओं के साथ अपना सफर शुरू किया। 1987 में नाहन ज़िला अस्पताल, 2009 से 2012 तक चिकित्सा अधीक्षक नाहन, 2013 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, धर्मपुर में चिकित्सा अधीक्षक, बिलासपुर में सीएमओ, 2015 में निदेशालय में संयुक्त निदेशक तथा 2018 से बतौर निदेशक पद पर सेवाऐं प्रदान कर रहे हैं।

द रीव टाइम्स ने प्रदेश में विभिन्न विभागों की योजनाओं और उनसे जुड़ी समस्याओं को आम पाठकों तक पहुंचाने के लिए 'इनसे मिलिए' संस्करण में हम सर्वप्रथम प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रदेश सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों पर खुलकर बात करने के लिए निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डॉ. अजय कुमार गुप्ता के साक्षात्कार के अंश पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। द रीव टाइम्स की ओर से संपादक हेम राज चौहान एवं सहायक संपादक अंजना ठाकुर ने निदेशक से बातचीत की।

द रीव टाइम्स : हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आम लोगों तक विभाग के क्या प्रयास रहें है ?

निदेशक : मुझे द रीव टाइम्स के साथ ये बात साझा करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं में हिमाचल प्रदेश आज बाकि राज्यों से बेहतर स्थिति में है। यहां दो सेक्टर पर ही स्वास्थ्य को लेकर लोगों की निर्भरता बनी हुई है। एक तो निजी और दूसरा सरकारी। स्वास्थ्य सेवाओं में 95 प्रतिशत भागीदारी सरकारी विभाग की ही है तथा आज हमारा प्रयास है कि गांव-गांव तक समस्त स्वास्थ्य सेवाओं को सुविधाजनक तरीक़े से पहुंचाया जाए जिसमें हम सफल हो रहे हैं।

द रीव टाइम्स : बहुत सी सरकारी योजनाओं को गांव तक प्रचार-प्रसार नहीं हो पा रहा है तथा उसका लाभ भी सभी नहीं उठा पा रहे हैं, इसके लिए विभाग के पास क्या योजना है?

निदेशक : हालांकि प्रदेश भर में स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है। फिर भी इसके लिए प्रसार-प्रचार का माध्यम विभाग अपने स्तर पर कर रहा है। जिसमें पंचायतों में जाकर ग्राम सभाओं में लोगों को जागरुक किया जा रहा है। स्कूलों में भी बच्चों को जानकारी दी जा रही है। स्वास्थ्य केन्द्रों पर आशा कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा इसे अमलीजामा पहनाया जा रहा है। प्रचार-प्रसार के अन्य माध्यमों को भी इसमें शामिल किया गया है।

द रीव टाइम्सः स्टेट हैल्थ कमीशन के सुझावों पर विभाग कितना खरा उतर पाया है ?

निदेशक : यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है। इस पर टिप्पणी नहीं कर पाउंगा।

द रीव टाइम्स : सहारा योजना 2019 क्या है ? इसका किस प्रकार लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं ?

निदेशक : यह एक वृहद् और बहुत ही लाभकारी स्वास्थ्य योजना है। कुछ ऐसे रोग हैं जो लंबी बीमारी का रुप ले लेते हैं तथा मंहगे भी होते हैं। इसमें रोगी को 2000/ प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसकी व्यापक जानकारी हर स्वास्थ्य केन्द्र पर ली जा सकती है।

द रीव टाइम्सः बारिशों का दौर नहीं थम रहा है। ऐसे में जल जनित रोग फैलने शुरु हो गए हैं और यह ख़तरा बना हुआ है। विभाग की ओर से क्या सार्थक क़दम उठाए जा रहे हैं ?

निदेशक : इसके लिए व्यापक पैमाने पर प्रचार-प्रसार कर पानी के समुचित उपयोग एवं साफ-सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित बनाया जा रहा है। स्कूलों, पंचायतों और स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से पंपलेट्स आदि बांट कर जानकारी दी जा रही है। विज्ञापनों का सहारा भी लिया जा रहा है।

द रीव टाइम्सः निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या योजना है ?

निदेशक : हिमाचल में एक योजना के अंतर्गत किसी भी फर्म अथवा उद्यमी को अपना अस्पताल खोलने की अनुमति के साथ-साथ अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य में सहभागिता योजना के अंतर्गत ऐसे उद्यमी को 25 एवं 5 प्रतिशत की मूल एवं ब्याज पर अनुदान की सुविधा दी जा रही है।

द रीव टाइम्सः क्या इसमें उद्यमियों की सहभागिता विभाग को सकारात्मक रुप से मिल रही है ?

निदेशक : नहीं, अभी जिस प्रकार की उम्मीद थी उस तरह से तो अभी परिणाम नहीं मिल पाऐं है लेकिन हमें आशा है कि शीघ्र ही इसमें निजी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी।

द रीव टाइम्स : देखा जा रहा है कि जन-औषधी दवाईयों को डॉक्टर नहीं लिख रहे हैं और मरीज़ों को मज़बूरन मंहगी दवाईयों को खरीदना पड़ रहा है। विभाग इस पर सख़्ती क्यों नहीं कर पा रहा है ?

निदेशकः ऐसा बिलकुल नहीं है। इसके लिए बाक़ायदा समय-समय पर ऑडिट होता है, इस पर भी नज़र रहती है कि डॉक्टर मरीज़ों को सस्ती दवाईयों को ही लिखे तथा शिकायत आने पर कार्यवाही की जाऐगी। हालांकि डॉक्टर जनऔषधि की सस्ती दवाईयों को पर्ची पर लिख रहे हैं।

द रीव टाइम्स : उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर क्या स्वास्थ्य कार्यकर्ता मरीज़ों को दवाईयां दे सकते हैं और क्या इंजेक्शन भी लगा सकते हैं ?

निदेशकः उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता कुछ दवाईयों को दे सकते हैं और इंजेक्शन यदि लगाना हो मरीज़ को जो डॉक्टर द्वारा लिखा गया हो तो वो भी लगा सकते हैं।

द रीव टाइम्सः पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स के लिए क्या कहना चाहते हैं ?

निदेशक : समाचार पत्र में सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। इस समाचार पत्र के माध्यम से लोगों को सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो रही है। मैं समाचार पत्र को शुभकामनाऐं देता हूं।

द रीव टाइम्स : प्रदेशवासियों को द रीव टाइम्स के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे ?

निदेशक : सभी स्वस्थ रहें और हिमाचल सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सभी को प्राप्त हो, हमारा निरंतर यही प्रयास है।

हिमाचल प्रदेश सरकार की सहारा योजना 2019 का विस्तृत विवरण पेज नं.14 पर है

जेलों में बंद 2450 कैदी उद्योगों में करेंगे काम, ईपीएफ भी कटेगा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल की 14 जेलों में बंद 2450 कैदी अब उद्योगों में काम कर अपनी आजीविका कमाएंगे। ये कैदी सुबह उद्योगों में काम करने जाएंगे और आठ घंटे ड्यूटी के बाद वापस जेल आ जाएंगे। प्रदेश की जेलों में 87 महिला कैदी भी हैं।

अन्य कर्मचारियों की तरह इन कैदियों का भी ईपीएफ कटेगा। कैदियों का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण हो, इसके लेकर जेल प्रशासन सरकार से बात कर रहा है। ऐसी व्यवस्था करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन जाएगा। जेलों में कैदियों की सकारात्मक व्यस्तता विषय पर शिमला में सोलह राज्यों के जेल अधिकारियों का दो दिवसीय सेमीनार में डीजी (जेल) सुमेश गोयल ने यह बात कही।

हाथ-हाथ को काम, जेल से जॉब तक इस योजना पर जेल प्रशासन काम कर रहा है। सुमेश गोयल ने कहा कि हिमाचल में अब जो जेलें बनेंगी वे औद्योगिक क्षेत्र के आसपास होंगी, ताकि कैदियों को रोजगार मिले।

अभी जेलों में कैदी तरह-तरह का सामान तैयार कर रहे है। शहरों और गांवों में कैदी गाड़ियों में अपने प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं। हिमाचल में इस समय 6 मोबाइल कैंटीन चलाई जा रही है। ये कैंटीनें शिमला, हमीरपुर, धर्मशाला जैसे शहरों में चलाई जा रही हैं।

होटलों के लिए सब्जियां काटने का काम कर रहीं महिला कैदी

सुमेश गोयल ने बताया कि पर्यटन सीजन के दौरान महिला कैदियों ने होटलों के लिए सब्जियां काटी हैं। महिला कैदियों ने एक सीजन में रिकॉर्ड 25 टन सब्जियां काटी हैं।हिमाचल में एनसीसी की यूनिफार्म बनाने का काम कैदी कर रहे हैं। आरकेएमवी एनसीसी छात्रों के लिए कैदी वर्दी तैयार करेंगे। हिमाचल में प्राइवेट स्कूलों में फर्नीचर तैयार करने का काम कैदी कर रहे है। शिमला के एसपीएस स्कूल का फर्नीचर कैदियों ने ही तैयार किया है। कैदी लोगों के घरों की छतें डालने का काम भी कर रहे हैं। कैदियों की कमाई का पैसा उनके बैंक खाते में जाते हैं, क्योंकि जेल प्रशासन ने कैदियों के बैंक खाते भी खोल रखे हैं।

हिमाचल में ई-सिगरेट पर अक्तूबर 2018 से रोक, तीन साल कैद की सजा का प्रावधान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल सरकार ने युवाओं को नशे के सामान से दूर रखने के लिए प्रदेश में अक्तूबर 2018 में ई सिगरेट की बिक्री, उत्पादन, आवंटन और विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। खाद्य सुरक्षा एवं विनियामक निदेशालय ने इसकी अधिसूचना जारी की थी।

आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर तीन साल तक कैद की सजा एवं पांच हजार तक जुर्माने का प्रावधान है। जयराम सरकार ने ई सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है।

इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन वितरण प्रणाली के तहत ई सिगरेट, ई निकोटिन फलेवर्ड हुक्का, हीट-नॉट बर्न डिवाइस की बिक्री पर भी प्रदेश में प्रतिबंध लगाया है। हिमाचल में सिंगल सिगरेट, खैनी और गुटखा बेचने पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है।

प्लास्टिक मुक्त होंगी हिमाचल की ग्राम पंचायतें, प्रारुप तैयार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र प्लास्टिक मुक्त होंगे। प्रदेश सरकार 3226 पंचायतों से प्लास्टिक कचरा खरीदेगी। पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए प्रारूप तैयार कर लिया है। सरकार ने प्लास्टिक खरीदने का रेट भी तय कर दिया है।

ग्रामीणों से यह प्लास्टिक 72 रुपये प्रति किलो खरीदा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के घरों से निकलने वाला किचन वेस्ट मैटेरियल में प्लास्टिक के कचरे को री-साइकल कर खाद तैयार करेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने कम से कम 10 पंचायतों का एक क्लस्टर तैयार करने का भी निर्णय लिया है।

जहां पर प्लास्टिक के कचरे एकत्रित किए जाएंगे और डंपिंग साइट में री-साइकल यूनिट भी बनेगी। पालमपुर के आइमा पंचायत में पहली यूनिट स्थापित हो चुकी है। जयराम सरकार ने प्रदेश में प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल बैठक में रिसाइकल न होने वाले प्लास्टिक वेस्ट तथा विभिन्न प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट की पुनः खरीद के लिए प्रस्तावित नीति को स्वीकृति दी। प्लास्टिक कचरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 72 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया है। यह दाम घरों से कूड़ा कचरा एकत्रित करने और उसे ग्राम पंचायत के पास जमा करने की एवज में निर्धारित किया है।

पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे हटाने एवं क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रारूप तैयार किया है। ग्रामीण लोगों से 72 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्लास्टिक कचरा खरीदेगी।

शिमला मिनी कॉन्क्लेव में 4775 करोड़ निवेश के 93 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राज्य सरकार की ओर से शिमला में हाल ही में मिनी कान्क्लेव का आयोजन किया गया। इस मिनी कॉन्क्लेव में मुख्य रूप से पर्यटन, आवास, शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, आईटी तथा आईटीईएस क्षेत्रों में निवेशकों से उत्साहवर्धक रूचि देखने को मिली है। 93 एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए, जो राज्य के लिए 4775 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करेंगे। इसमें अकेले पर्यटन क्षेत्र से संबंधित 47 समझौता ज्ञापन शामिल हैं।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला में आयोजित मिनी कॉन्क्लेव की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि देश के सभी प्रमुख राज्य निवेशकों को लुभाने के लिए इस तरह के इन्वेस्टर मीट का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों ने भी अंतर्राष्ट्रीय रोडशो आयोजित किए लेकिन हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित जर्मनी, नीदरलैंड और यूएई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रोडशो और दिल्ली, बैगलूरू, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद और चंडीगढ़ में घरेलू रोडशो में निवेशकों से इस प्रदेश में निवेश करने के प्रति विशेष रूचि देखने को मिली है।

हाल ही में कुल्लू जिले के मनाली में भी इस तरह के मिनी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसमें 2219 करोड़ रुपये के निवेश के 93 एमओयू हुए थे।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय उद्यमियों से ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का हिस्सा बनने का आग्रह किया और इस तरह राज्य के विकास में अपना योगदान देने का भी आग्रह किया।

शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट का संकल्प और इसे आयोजित करने का निर्णय मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के दूरदर्शी नेतृत्व में लिया गया है, जिसका लक्ष्य प्रदेश में 85000 करोड़ रूपये का निवेश आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि आवास और शहरी विकास क्षेत्र में निवेश की अपार सम्भावनाएं हैं।

हिमाचल में दूसरी से पांचवीं तक बच्चे पढ़ेंगे संस्कृत, 17 सदस्यीय कमेटी गठित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश भर के दूसरी से पांचवीं तक के बच्चे अब हिंदी और अंग्रेजी के साथ संस्कृत की पढ़ाई भी करेंगे। इसके लिए राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कवायद शुरू कर दी है। स्कूलों में दूसरी कक्षा से संस्कृत का पाठ्यक्रम और विषय शुरू करने में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों पर मंथन होगा।

इसके लिए बोर्ड ने प्रदेश भर के महाविद्यालयों, स्कूलों और संस्कृत के क्षेत्र में काम कर रहीं संस्थाओं के पदाधिकारियों की 17 सदस्यीय कमेटी गठित की है। यह कमेटी बोर्ड को पाठ्यक्रम सहित अन्य सुझाव देगी।

उधर, राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव धर्मेश रामोत्रा ने बताया कि दूसरी कक्षा से संस्कृत शुरू करने के लिए बोर्ड ने कवायद शुरू कर दी है। स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षकों से इस संबंध में सुझाव लिए जाएंगे।

राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नई शिक्षा नीति में बच्चों को त्रिस्तरीय भाषा आधार पर पढ़ाई करवाने का प्रस्ताव एमएचआरडी को भेजा है। इसमें नई शिक्षा नीति में स्कूलों में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने की पैरवी की गई है। इससे स्कूली बच्चों की भाषा पर अच्छे से पकड़ बन सके। संस्कृत भाषा में 102 अरब शब्दों का संग्रह है। विश्व भर में सबसे अधिक शब्दों वाली एकमात्र संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा के कई शब्दों का प्रयोग अन्य भाषाओं में भी होता है।

केंद्रीय एजेंसियों के अलर्ट के बाद हरकत में हिमाचल पुलिस, ड्रोन से हो रही निगरानी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और मिलिट्री इंटेलिजेंस की आतंकी हमले की सूचनाओं के बाद हिमाचल पुलिस के अलर्ट का ग्राउंड पर असर दिखना शुरू हो गया है। हिमाचल पुलिस कहीं ड्रोन की मदद से निगरानी में जुट गई है तो पंजाब से लगते ऊना और कांगड़ा जिले की सीमाओं पर नाके बढ़ाकर वाहनों को चेकिंग के बाद ही प्रदेश में प्रवेश दे रही है। वैसे तो अधिकारी अलर्ट को सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन इस बार एहतियात ज्यादा बरते जा रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट के बाद हिमाचल पुलिस ने सूबे के भाखड़ा बांध जैसे सामरिक व विशेष महत्व के प्रतिष्ठानों और शक्ति पीठों की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-नेपाल पाइपलाइन का उद्घाटन किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल और भारत के आपसी सहयोग को रेखांकित करते हुए कहा कि यह पाइपलाइन समय से पहले पूरा हो गया।

यह दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस-बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन नेपाल के लिए बड़ा बदलाव लायेगा और वहां तेल भंडारण की समस्या से निजात दिलाने में सहायता करेगा। इस परियोजना के द्वारा कीमत में कमी आयेगी और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस परियोजना के तहत नए क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के लिए नए अवसरों का लाभ मिलेगा।

IIFA Awards 2019 आलिया भट्ट और रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर अवॉर्ड

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हाल ही में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी (आईफा) पुरस्कारों की घोषणा की गयी। इस साल आइफा अवॉर्ड्स को 20 साल पूरे हो गए हैं। मनोरंजन जगत का सबसे बड़ा अवॉर्ड फंक्शन काफी समय बाद इस बार मुंबई में आयोजित हुआ। बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड इस बार राजी को मिला है। राजी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड आलिया भट्ट को मिला है। राजी फिल्म एक भारतीय जासूस की कहानी है, जिसका किरदार आलिया भट्ट ने निभाया है। फिल्म पद्मावत के लिए बेस्ट एक्टर (मेल) का अवॉर्ड रणवीर सिंह को मिला है।

एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया वायुसेना के नए चीफ

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्र सरकार ने एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को वायु सेना का नया प्रमुख नामित किया है। आरकेएस भदौरिया वर्तमान में वायु सेना प्रमुख हैं। वे एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ का स्थान लेंगे। बीएस धनोआ 30 सितंबर 2019 को चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद से रिटायर हो गए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पासआउट आरकेएस भदौरिया के पास 4,250 घंटे उड़ान का अनुभव है। आरकेएस भदौरिया के पास 26 प्रकार के लड़ाकू और परिवहन विमान उड़ाने का अनुभव है। वे 15 जून 1980 को वायु सेना के लड़ाकू दस्ते में शामिल हुए थे। भारतीय वायु सेना के नियमानुसार वे इस पद पर तीन साल तक या फिर 62 साल की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकते हैं। हालांकि वे इस हिसाब से केवल दो साल तक ही इस पद पर बने रह पाएंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस में उड़ान भरने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 सितम्बर 2019 को बेंगलुरु में स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में सफल उड़ान भरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस में उड़ान भरकर एक नया इतिहास रच दिया है। वे तेजस में उड़ान भरने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री बन गये हैं। तेजस विमान को तीन साल पहले ही भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु के एचएएल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले लड़ाकू विमान सुखोई में उड़ान भरी थी। सुखोई दो इंजन वाला लड़ाकू विमान है वहीं तेजस एक इंजन वाला लड़ाकू विमान है।

ई-सिगरेट पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर कड़ी सजा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्र सरकार ने ई-सिगरेट के उत्पादन तथा बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब ई-सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, विनिर्माण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया जायेगा। यह निर्णय केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि ई-सिगरेट समाज में एक नई समस्या को जन्म दे रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि ई-सिगरेट को बनाना, आयात या निर्यात, बिक्री, वितरण, स्टोर करना तथा विज्ञापन करना सब पर प्रतिबंध होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेस के दौरान कहा कि ई-सिगरेट ऑर्डिनेंस 2019 को मंत्रियों के समूह ने समय पहले ही इस पर पूरी तरह से विचार विमर्श किया था। मोदी सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे में ई-सिगरेट पर भी प्रतिबंध लगाना शामिल था।

मोती बाग: भारतीय किसान के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑस्कर के लिए नामित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

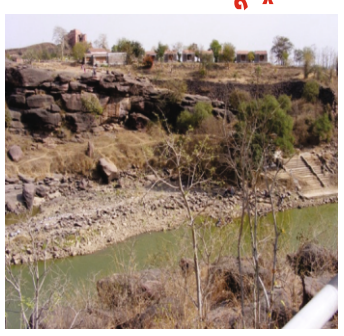

मोती बाग, उत्तराखंड के किसान के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। निर्मल चंद्र डंडरियाल द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म, विद्यादत्त शर्मा नामक एक किसान के जीवन पर आधारित है, जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक दूरदराज के गांव से संबंधित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिल्म के 'ऑस्कर' की रेस में पहुंचने पर खुशी जाहिर की।

उन्होंने फिल्म के निर्देशक निर्मल चंद्र डंडरियाल को बधाई देते हुए कहा कि फिल्म गांव के युवाओं को उनके गांवों में रहने और उनके समुदायों में योगदान करने हेतु प्रेरित करेगी।

ईपीएफओ ने 6 करोड़ से अधिक खाताधारकों के लिए बढ़ाई ब्याज दर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 6 करोड़ से अधिक सदस्यों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने इसकी जानकारी दी। पिछले दो वर्षों में, यह कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की ब्याज दर में पहली वृद्धि है। वर्तमान में, ईपीएफओ द्वारा 8.55 प्रतिशत की ब्याज दर से भुगतान किया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2017-18 में ब्याज दर 8.55 प्रतिशत थी। अब ब्याज दरों में 0.10 प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ देश के 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा। पीएफ पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच अगस्त 2019 में ब्याज दर को लेकर सहमति बन गई थी।

भारत ने हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण सुखोई - 30 एमकेआई लड़ाकू विमान से किया गया था। इस मिसाइल ने पश्चिम बंगाल में एक हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिसा के तट पर किया गया है। यह मिसाइल परीक्षण के दौरान अपने निशाने पर सटीक वार किया। अस्त्र मिसाइल पूरी तरह से देश में बनी है। अस्त्र मिसाइल 'बीवीआर' (बियोंड विजुअल रेंज) हवा से हवा मारक क्षमता वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर है।

दिनेश मोंगिया ने क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास की घोषणा की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर दिनेश मोंगिया ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लगभग 12 साल बाद क्रिकेट के सभी प्रारुपों को अलविदा कह दिया है। गांगुली की कप्तानी में साल 2003 विश्व कप के दौरान दिनेश मोंगिया भारतीय टीम का हिस्सा थे। दिनेश मोंगिया ने साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपना डेब्यू किया था। दिनेश मोंगिया मैदान पर आखिरी बार पंजाब के लिए साल 2007 में क्रिकेट मैच खेले थे।

व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राश्ट्रीय पेंशन योजना दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों तथा स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए है जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। इस योजना के अंतर्गत भावी लाभार्थियों के लिए नामांकन की सुविधा देश भर में स्थित 3.50 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। इस योजना के तहत व्यापारी अपने नजदीकी सीएससी पर जाकर नामांकन करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के अहम योगदान को देखते हुए व्यापारियों तथा स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना को मंजूरी दी है। यह पेंशन योजना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरे कार्यकाल की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस योजना में साल 2019-20 तक 25 लाख लाभार्थियों तथा साल 2023-2024 तक 2 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

DRDO ने पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय सेना के लिए थर्ड जेनरेशन की एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल की जरुरत को ध्यान में देखते हुए इसे तैयार किया गया है। डीआरडीओ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार परीक्षण के दौरान मिसाइल को एक ट्रायपॉड से फायर किया गया और इसके निशाने पर एक टैंक था। मिसाइल ने टॉप अटैक मोड में लक्ष्य को निशाना बनाया और पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह मिसाइल किसी भी ऊंची पहाड़ी पर या दुर्गम स्थल पर आसानी से लाई जा सकती है। इसकी एक विशेषता है कि इसे दिन और रात दोनों समय उपयोग में लाया जा सकता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि आमने-सामने की लड़ाई में यह मिसाइल बेहद कारगर सिद्ध होती है। सेना के लिए 2021 तक इस मिसाइल का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जायेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषण के 12,652 करोड़ रुपये की लागत वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 500 मिलियन से अधिक पशुधन का टीकाकरण है। इसके अंतर्गत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर को मुखपका - खुरपका रोग से बचाना है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना तथा उनकी आय को दोगुना करना है, जैसा कि केंद्रीय बजट के तहत वादा किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा कार्यक्रम से 100 प्रतिशत धन प्राप्त होगा। केंद्र सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के लिए साल 2019 से साल 2024 के लिए 12,652 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना से करोड़ों किसानों को फायदा होगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य पशुजन्य माल्टा-ज्वर से बचाव हेतु प्रत्येक साल दुधारू पशुओं के 36 मिलियन मादा बच्चों को टीका लगाना है।

गुजरात सरकार ने न्यू मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन की जुर्माना राशि कम की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

गुजरात सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए वसूले जाने वाले जुर्माने की राशि लगभग 50 प्रतिशत की कमी की है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नए जुर्माने की घोषणा की। गुजरात में यातायात उल्लंघन के लिए नए नियम 16 सितंबर 2019 से लागू किए गये। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा की सड़क दुर्घटनाओं के वजह से प्रत्येक साल हजारों निर्दोष लोगों को जान गंवानी पडती है। गुजरात सरकार ने बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की स्थान पर अब 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकार के अनुसार, कार में बिना सीट बेल्ट बांधे चार पहिया वाहन चलाने पर 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। सरकार ने बिना लाइसेंस बाइक चलाने पर 5000 रुपये के स्थान पर 2000 रुपये और बिना लाइसेंस कार चलाने पर 3000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया है।

9/11 हमले के बाद ऐसे संभला अमेरिका

द रीव टाइम्स ब्यूरो

9/11 हमले ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इन हमलों ने पश्चिमी देशों को आतंकवाद के उस चेहरे से आमने - सामने कराया जिसे पहचानने से हर किसी ने इंकार कर दिया था। 18 साल के बाद भी इस घटना ने लोगों का पीछा नहीं छोड़ा है. आतंकी संगठन अल-कायदा ने 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर आत्मघाती हमला किया। अल कायदा आतंकवादियों ने उस दिन चार यात्री विमानों का अपहरण किया था। इस पूरे हमले में 3000 से अधिक लोग मारे गए थे तथा लगभग 6,000 अन्य लोग घायल हो गए थे। यह हमला इतना बड़ा था कि इस हमले में लगी आग को बुझाने में करीब 100 दिन का समय लगा था। आतंकवादियों ने हवाई जहाज को मिसाइल के रूप में उपयोग किया था।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

पाक से बात को तैयार लेकिन आतंकवाद से नहीं –विदेश मंत्री जयशंकर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत - पाकिस्तान बातचीत को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान से बात करने में कोई समस्या नहीं है लेकिन हमें टेररिस्तान से बात करने में समस्या है। पाकिस्तान को टेररिस्तान बताते हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए आतंकवाद की पूरी इंडस्ट्री बनाई है। भारत, ऐसे देश से बात नहीं कर सकता जो आतंकवाद को प्रायोजित करता है। एस जयशंकर ने मंगलवार को एशिया सोसायटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष केविन रुड को दिए एक इंटरव्यू के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा, उन्हें इस बात को स्वीकार करना होगा कि जो मॉडल (आतंकवाद) उन्होंने तैयार किया है, वह अब काम नहीं करता। आप इस दौर में ऐसा नहीं कर सकते। आप आतंकवाद का उपयोग करते हुए अपनी नीति का संचालन करते हैं, जो आपके देश की सरकार के मुख्य केंद्र बिंदु में है। देखिए हमें पाकिस्तान से बातचीत में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम टेररिस्तान से बातचीत नहीं कर सकते। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में एकबार फिर साफ कर दिया कि भारत, पाकिस्तान से बातचीत से इनकार नहीं करता है लेकिन उससे पहले आतंकवाद पर पाकिस्तान को कोई ठोस कदम उठाना होगा।

एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में आने की कगार पर पहुंचा पाकिस्तान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब उस पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में आने का खतरा मंडराने लगा है।

एफएटीएफ द्वारा फिलहाल पाक को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है और उससे बाहर आने के लिए पाकिस्तान को एफएटीएफ द्वारा दिए गए 27 बिंदुओं के एक्शन प्लान पर अमल करना था, लेकिन वह उसका भी पालन करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एफएटीएफ की टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली विंग के सामने आया है कि पाकिस्तान ने 27 बिंदुओं में से सिर्फ 6 बिंदुओं पर ही अमल करते हुए कार्रवाई की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ पाकिस्तान को अगर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिलने वाली आर्थिक मदद पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अक्तूबर में एफएटीएफ द्वारा पेरिस में होने वाली मीटिंग में उसके स्टेटस का रिव्यू किया जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उद्देश्य मनी लान्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और अन्य आर्थिक मसलों को लेकर मानक तय करना और उनका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन कराना होता है।

इसमें लीगल, रेग्यूलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स भी शामिल होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स

के मुताबिक पाकिस्तान द्वारा लागू किए जा रहे एफएटीएफ के एक्शन प्लान पर नजर रखने वाली टीम के अनुसार यूएन द्वारा घोषित किए गए 100 से ज्यादा आतंकियों में से पाकिस्तानी सरकार ने अब तक सिर्फ 5 की ही उनके देश में होने की पहचान करते हुए लोकेट किया है।

नीदरलैंड में एक हफ्ते तक मनाई जाएगी 150वीं गांधी जयंती, कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के मौके पर नीदरलैंड में गैर-हिंसा के लिए गांधी मार्च समेत कई सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम भारतीय दूतावास द्वारा गांधी नॉन-वॉयलेंस फाउंडेशन और अन्य समूहों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। जिसमें एक साइकिल रैली, महात्मा गांधी के जीवन पर एक प्रदर्शनी और एक स्मरणोत्सव बैठक शामिल हैं। भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा यह उत्सव 29 सितंबर को गांधी के सादगी और स्थिरता वाले विचारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल रैली के साथ शुरू किया गया है। हेग शहर में रैली भारत के दूतावास से शुरू होगी और प्रतिष्ठित पीस पैलेस, पार्लियामेंट और सबसे लोकप्रिय समुद्र तटीय रिसॉर्ट से गुजरते हुए भारतीय दूतावास में वापसी करेगी। 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक, लाइफ एंड मैसेज ऑफ गांधी पर एक प्रदर्शनी का आयोजन हेग के सिटी हहल के एट्रियम में किया जाएगा।

डच में प्रदर्शनी दर्शकों को महात्मा गांधी के जीवन के महत्वपूर्ण चरणों को दिखाएगी। 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक वॉलंटीयर्स नीदरलैंड के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में फॉलो द महात्मा अभियान चलेगा और गांधी के अहिंसा के संदेश और आज की दुनिया में इसकी प्रासंगिकता के बारे में बताया जाएगा। इस स्कूल परियोजना के जरिए 25 से अधिक स्कूलों और 1,600 से अधिक बच्चों तक पहुंचा जाएगा।

ईरानी सेना की चेतावनी, हमला करने वाला देश 'युद्ध का मैदान' बन जाएगा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सऊदी अरब के अरामको तेल प्लांट पर हुए हमले के बाद से ही अमेरिका और सऊदी अरब, इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ईरान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है लेकिन अमेरिका लगातार इसे तूल दे रहा है।

अब इन बयानों के जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हुसैन सलामी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर कोई भी देश ईरान पर हमले की

योजना बना रहा है तो वह युद्ध के परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहे। सलामी ने कहा कि अगर कोई भी देश उनपर हमला करता है तो वह देश युद्ध का मैदान बनने के लिए तैयार रहे। अगर इसके बाद भी वह यही चाहते हैं तो आगे बढ़ें। सलामी ने ये बातें तेहरान में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं। सलामी ने साथ ही कहा कि वो ईरान को युद्ध का मैदान कभी नहीं बनने देंगे। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि, सावधान रहें, यह आक्रामकता सीमित नहीं रहेगी। हम सभी हमलावर देशों का पीछा करेंगे।

जम्मू–कश्मीर पर यूरोपीय यूनियन के सांसदों ने किया भारत का समर्थन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर यूरोपीय यूनियन (ईयू) के वरिष्ठ सांसद हर्वे जुवीन समेत कई सांसदों ने भारत के समर्थन का एलान किया है।

सांसदो ने कहा है कि यह भारत का अंदरूनी मसला है, इस पर किसी तरह के विदेशी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे लिए कश्मीर मसला भारत का अंदरूनी मसला है। हम भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं। हमें इस मामले को अंतरराष्ट्रीय रूप देने के प्रयासों से भी सावधान रहना है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान लगातार जम्मू - कश्मीर मामले पर अपना तीखा विरोध व्यक्त कर रहा है और दुष्प्रचार से मामले पर विश्व बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। भारत ने पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उसे केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया था। जम्मू - कश्मीर में शामिल रहे लद्दाख को अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया है। बौखलाए पाकिस्तान और चीन भारत सरकार के इस कदम पर लगातार विरोध जता रहे हैं। इससे पहले यूरोपीय सांसदों रेज्जर्ड कज्नेकी और फुल्वियो मार्टुसिएलो ने यूरोपीय संसद की पूर्ण बहस की विशेष बहस के दौरान कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया और भारत को एक महान लोकतंत्र बताया।

उन्होंने बताया कि आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान ने जम्मू - कश्मीर का नारा दिया। इससे पहले यूरोपीयन कंजर्वेटिव एंड रिफॉर्मिस्ट ग्रुप के ज्योफ्रे वैन अहर्डेन ने कहा कि पाक ने शुरू से ही नियंत्रण रेखा के पार दमन और आतंकवाद का समर्थन करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है।

अमेरिका और भारत के बाद अब ई सिगरेट पर चीन भी पाबंदी को तैयार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिका और भारत के बाद अब चीन ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। चीन एक राज्य समाचार एजेंसी के अनुसार देश इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में इस्तेमाल होने वाले तरल पदार्थ और अन्य चीजों पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। चीन ने यह फैसला ई-सिगरेट के चलते होने वाली बीमारियों और मौत को लेकर जताई गई वैश्विक चिंता की वजह से लिया है।

जानकारी के अनुसार इसे लेकर नियम का अगले महीने तक जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी इस बात के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं कि इसपर किस तरह के प्रतिबंध लगाए जाने वाले हैं।

बता दें कि पिछले दिनों भारत में ई सिगरेट के बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। यही नहीं अमेरिका समेत कई अन्य देशों ने भी इसपर रोक लगा दी है। ई सिगरेट की वजह से बढ़ते मौत के आंकड़ों पर विश्व के कई देशों ने चिंता जताई है और कुछ देशों में इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है तो कुछ देशों मे इस पर आंशिक प्रतिबंध है। भारत में पिछले हफ्ते इसके बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। इसका पहली बार उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ एक साल तक की अधिकतम कैद या दोनों का प्रावधान किया गया है। दूसरी बार में 5 लाख रुपये का जुर्माना और तीन साल की जेल या दोनों का प्रावधान है। इसमें ई हुक्का भी शामिल है।

NASA का दावा – तीन अरब साल पहले रहने लायक था शुक्र

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सौर मंडल का दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में दावा किया है कि तीन अरब साल पहले इस ग्रह पर भी पानी मौजूद था। वैज्ञानिकों का मानना है कि तीन अरब साल पहले शुक्र ग्रह पर भी पानी मौजूद था, लेकिन 700 मिलियन यानी 70 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड में हुए नाटकीय बदलावों के कारण इस ग्रह के 80 फीसद क्षेत्र का निर्माण दोबारा हुआ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अध्ययन में यह बात सामने आई है। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह अध्ययन शुक्र ग्रह की जलवायु के इतिहास का एक नया दृष्टिकोण देता है और उम्मीद जताता है कि शुक्र के जैसे एक्सोप्लेनेट्स (सौरमंडल के बाहरी ग्रह) में जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। चालीस साल पहले नासा के पायनियर वीनस मिशन ने अध्ययन में यह पाया था कि पृथ्वी के नजदीकी ग्रह में उथले महासागर का पानी हो सकता है। यह देखने के लिए कि क्या शुक्र की जलवायु ऐसी है कि वहां कभी पानी ठहरा हो सकता है, अमेरिका में नासा गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज (जीआइएसएस) के शोधकर्ताओं ने सिमुलेशन के जरिये शुक्र में पानी के विभिन्न स्तरों की एक श्रृंखला बनाई, जिसे पांच भागों में बांटा गया।

जलवायु परिवर्तन का असर, भारत में बिजली संयंत्रों के लिए पैदा हो सकता है बड़ा जलसंकट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जलवायु परिवर्तन और जलमार्गों के चलते आने वाले दिनों में भारत में बिजली संयंत्रों के लिए पानी का संकट पैदा हो सकता है। भारत ही नहीं चीन समेत एशिया के विकासशील देशों के लिए अपने बिजली संयंत्रों को शीतल रखने के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। एक अध्ययन में यह सनसनीखेज जानकारी दी गई है। बता दें कि भारत में नदी जलमार्ग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए नदी में एक तय मात्र में पानी का होना जरूरी है। एनर्जी एंड एनवायरमेंट साइंस नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक कोयला को जलाकर बिजली पैदा करने वाले मौजूदा और आगामी बिजली संयंत्र इसके सबसे बड़े शिकार हो सकते हैं। अमेरिका की ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर जेफ्रे बीलिक्की ने कहा, 'जलवायु परिवर्तन का एक असर यह हुआ है कि मौसम बदलने लगा है, इसके चलते कहीं बहुत ज्यादा मानसूनी बारिश हो रही है तो कहीं भीषण सूखा पड़ रहा है।' बीलिक्की ने कहा, 'बिजली संयंत्रों-कोयला, परमाणु और प्राकृतिक गैस से चलने वाले-को शीतलता (कूलिंग) के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जब बारिश नहीं होगी तो नदियों में पानी भी नहीं होगा और आप बिजली संयंत्रों को ठंडा नहीं कर सकेंगे।' अमेरिका में कुछ बिजली संयंत्रों के लिए यह समस्या पैदा भी हो गई है। खासकर गर्मी के मौसम में इन बिजली संयंत्रों को पानी की सप्लाई कम हो जा रही है।

रुस के बाद चीन पहुंचे तालिबान के प्रतिनिधि, अफगान शांति प्रयासों पर की चर्चा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिका के साथ शांति वार्ता विफल होने के बाद तालिबान के प्रतिनिधि चीन पहुंचे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में शांति प्रयासों को लेकर चीनी अधिकारियों के साथ चर्चा की। तालिबान के प्रतिनिधि पिछले हफ्ते रूस भी गए थे और अफगान मामलों पर रूस के विशेष दूत जमीर काबुलोव से मुलाकात की थी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में तालिबान का नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। बरादर कतर स्थित तालिबान के सियासी दफ्तर का प्रमुख है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि बरादर और मंत्रालय के अधिकारियों ने अफगानिस्तान में शांति प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने अमेरिका से शांति प्रयासों को बरकरार रखने की अपील करते हुए कहा कि इसमें चीन सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इससे पहले तालिबान प्रवक्ता मुहम्मद सोहेल शाहीन ने ट्वीट में बताया था कि नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चीन के दौरे पर है और उसने अफगानिस्तान मामले में चीन के विशेष दूत डेंग शीजून से मुलाकात की। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गत आठ सितंबर को तालिबान के साथ चल रही शांति वार्ता रद कर दी थी। उन्होंने यह कदम अफगानिस्तान में तालिबान के हमले में एक अमेरिकी सैनिक की मौत के बाद उठाया था। उन्होंने यह कदम ऐसे समय पर उठाया जब दोनों पक्ष समझौते की दहलीज पर थे। अमेरिका और तालिबान के बीच गत दिसंबर से कतर की राजधानी दोहा में शांति वार्ता चल रही थी।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

करंट अफेयर्स

THE CURRENT AFFAIRS 2019

- महाराष्ट्र सरकार, संयुक्त राज्य व्यापार और विकास एजेंसी की मदद से जितने करोड़ रुपए की लागत से आपदा प्रबंधन उपकरण लगाने का प्रयास कर रही है ताकि राज्य में बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके - 140 करोड़ रुपए
- वह राज्य सरकार जिसने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा की है - उत्तर प्रदेश
- जिस देश ने अंतरिक्ष में पहली बार भेजे गए अपने ह्यूमनॉयड (इंसान जैसे) रोबोट 'Fedor' की सेवा समाप्त कर दी है - रूस
- डेनमार्क के माइक्रोबायोलॉजिस्ट की 166वीं जयंती के अवसर पर गूगल ने डूडल के जरिये जिन्हें याद किया - हैंस क्रिश्चियन ग्राम
- नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के जितने एयरपोर्ट्स सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हो चुके हैं - 55
- हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ऑड - इवन स्कीम को 4 से 15 नवंबर की अवधि में लागू किये जाने की घोषणा की गई - दिल्ली
- वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसमें सूखे की समस्या से निपटने के लिए Draught Toolbox की घोषणा की गई - UNCCD COP14
- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में जिस राज्य में लक्कमपल्ली नामक स्थान पर मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया - तेलंगाना
- भारतीय थल सेना ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और असम में पहले एकीकृत युद्ध समूह के साथ जिस प्रमुख अभ्यास का आयोजन करने जा रही है - हिम विजय
- DRDO दवारा हाल ही में जिस राज्य में पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है - आन्ध्र प्रदेश
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्थान से स्वच्छता ही सेवा - 2019 नामक पहल का शुभारंभ किया है - मथुरा
- वह खिलाड़ी जिसे गृह मंत्रालय द्वारा पद्म विभूषण के लिए नामांकित किया गया है - मैरी कॉम
- वह देश जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 79वां सदस्य बना है - सेंट विन्सेंट एंड ग्रेनाडिन्स
- वह संगीत निर्देशक जिसे महाराष्ट्र सरकार के 'लता मंगेशकर अवार्ड' के लिए चुना गया है - ऊषा खन्ना
- वह शहर जिसमें यूरेशियन आर्थिक फोरम का आयोजन किया गया - शीआन
- भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्तूबर, 2019 से सभी बैंकों के लिये नए फ्लोटिंग रेट लोन को इससे जोड़ना अनिवार्य कर दिया है - एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट
- हाल ही में एक गैर - सरकारी उपक्रम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वह शहर जिसमें सबसे अधिक स्टार्ट अप्स मौजूद हैं - नई दिल्ली
- वह देश जिसके पूर्व राष्ट्रपति बचरुद्दीन जुसुफ हबीबी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया - इंडोनेशिया
- जिसे हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है - जस्टिस विक्रम नाथ
- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शहर में देश का पहला 'मेक इन इंडिया मेट्रो कोच' लॉन्च किया है - मुंबई
- भारत और जिस देश के बीच नई दिल्ली में छठी रणनीतिक आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया था - चीन
- हाल ही में जिस देश के खगोलविदों ने पृथ्वी के वायुमंडल का एक फिंगरप्रिंट बनाया है - कनाडा
- केंद्र सरकार ने जम्मू - कश्मीर की परिसंपत्ति तथा देनदारी के वितरण के लिए जितने सदस्यीय समिति का गठन किया है - तीन
- अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल पत्रिका The Lancet द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया से जिस वर्ष तक मलेरिया समाप्त किया जा सकता है - 2050
- जिस एनआरआई उद्योगपति को ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए नामित किया गया है - रामी रेंजर
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस देश के साथ संयुक्त रूप से दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस-बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया है - नेपाल
- भारत और जिस देश के बीच छठी रणनीतिक आर्थिक वार्ता (एसईडी) नई दिल्ली में संपन्न हुई जिसमें दोनों पक्षों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु सहमत हुए - चीन
- वह राज्य जिसके मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में नीलगिरी तहर की संख्या में पिछले 3 वर्ष में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है - तमिलनाडु
- एयर इंडिया अपने यात्रियों के लिये जिस नाम से नई सेवा योजना शुरू कर रही है - नमस्कार सेवा
- महाराष्ट्र की ग्रामीण सड़कों को पक्का कर राज्य में संपर्क ढाँचा बेहतर बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) जितने करोड़ डॉलर का ऋण देगा - 20 करोड़ डॉलर
- भारत सरकार ने चक्रवाती तूफान डोरियन से प्रभावित जिस देश को तुरंत 10 लाख डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है - बहामास
- पाकिस्तान के प्रसिद्ध पूर्व लेग स्पिनर जिनका हाल ही में 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया - अब्दुल कादिर
- 28वें इंडो - थाई CORPAT अभ्यास का आयोजन जिस शहर में किया जा रहा ह - बैंकाक
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों पर आधारित पुस्तक का यह नाम है जिसका दूसरा संस्करण हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया - लोकतंत्र के स्वर
- हाल ही में जिस देश के वैज्ञानिकों की एक टीम ने कंकालों का अध्ययन कर डायनासोर की एक नई प्रजाति की पहचान की है - जापान
- वह राज्य जिसके मंत्रिमंडल ने हाल ही में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए एक विशेष बाघ संरक्षण बल बनाने का निर्णय लिया है - उत्तराखंड
- हाल ही में जिस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने गुरु नानक देव की रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया है - यूनेस्को
- हाल ही में जिस भारतीय ने दुनिया की सबसे कठिन मानी जानी वाली रेस 'एंडुरोमन ट्रायथलन' को रिकॉर्ड समय में जीत लिया है - मयंक वैद
- हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने जिस शहर में 'समुद्री संचार सेवा' का शुभारंभ किया - मुंबई
- हाल ही में जिस राज्य सरकार ने चोरी हुए मोबाइल्स फोन को ट्रैक करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है - महाराष्ट्र सरकार
- हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर जिस भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को नियुक्त किया गया है - कपिल देव
- जिस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है - राजस्थान
- जिसे आन्ध्र प्रदेश का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है - जस्टिस पी. लक्ष्मण रेड्डी
- विश्व ओजोन दिवस जिस दिन मनाया जाता है - 16 सितंबर
- हाल ही में भारत और स्लोवेनिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जितने समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये - सात
- भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच जिस स्थान पर 16 से 20 सितम्बर के दौरान त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया - पोर्ट ब्लेयर
- दूरदर्शन की स्थापना के हाल ही में जितने वर्ष पूरे हुए हैं - 60 वर्ष
- स्वच्छ कोयला अनुसन्धान व विकास के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन जिस स्थान पर किया गया है- IISC बेंगलुरू
- हाल ही में भारतीय नौसेना और जिस देश की शाही नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्याभ्यास 'समुद्र लक्ष्मण' में भाग लिया था - मलेशिया
- इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में फिल्म 'द लास्ट कलर' के लिए जिसे बेस्ट ऐक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है - नीना गुप्ता
- अभियंता दिवस जिस दिन मनाया जाता है - 15 सितंबर
- भारत की पाँच महिला पुलिस अधिकारियों को जिस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन में उत्कृष्ट सेवाओं हेतु सम्मानित किया गया है - दक्षिण सूडान
- हाल ही में सोलोमन द्वीपसमूह ने जिस देश के साथ अपने राजनीतिक संबंधों की समाप्ति की घोषणा की है - ताइवान
- हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर ने अंतिम ODI खेलने के 12 साल बाद क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है - दिनेश मोंगिया
- EPFO ने 6 करोड़ खाताधारकों को वर्ष 2018–19 के लिए जितना प्रतिशत ब्याज दिए जाने की घोषणा की है - 8.65 प्रतिशत
- डीआरडीओ द्वारा सुखोई - 30 विमान से हवा - से - हवा - में मार करने वाली जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया - अस्त्र
- रेलवे मंत्रालय द्वारा अब तक जितनी रेलगाड़ियों को 'हैड ऑन जेनरेशन टेक्नोआलॉजी' (HOG) में परिवर्तित किया जा चुका है - 342
- एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष का नाम जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है - ताकेहिको नाकाओ
- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने जिस राज्य में अदरक की दो नई प्रजातियों की खोज की है - नागालैंड
- हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रथम सैन्यै चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन जिस शहर में किया गया - नई दिल्ली
- वह राज्य जिसके पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को राज्य के गृह विभाग ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया है - जम्मू-कश्मीर
- तेलंगाना विधानसभा ने नल्लामाला वनों में जिस रासायनिक तत्व के खनन रोकने हेतु प्रस्ताव पारित किया है - यूरेनियम
- हाल ही में जिस संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व में भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक रही - संयुक्त राष्ट्र
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जिस दिन प्रथम विश्व मरीज सुरक्षा दिवस मनाया गया - 17 सितंबर
- बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों के निर्देशन के लिए प्रसिद्ध जिस निर्देशक का हाल ही में 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया - श्याम रामसे
- हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में तीसरी से लेकर आठवीं कक्षा तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया है - उत्तराखंड सरकार
- भारत ने जिस योजना के तहत जुलाई 2019 में 1.69 बिलियन डॉलर का अब तक का उच्चतम मासिक प्रवाह दर्ज किया है - उदारीकृत प्रेषण योजना
- बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका में जिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया - डॉ. कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार
- हाल ही में जिस राज्य ने वनों के निकटवर्ती क्षेत्रों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने हेतु बायो - फेंसिंग के प्रयोग का फैसला किया है - उत्तराखंड
- IIFA अवार्ड्स 2019 में जिसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब हासिल हुआ - आलिया भट्ट
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जिसे नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है- रॉबर्ट ओ ब्रायन
- हाल ही में राजनाथ सिंह जिस स्वदेश निर्मित विमान में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बने - तेजस
- हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है - तेलंगाना
- उत्तर प्रदेश का जो विश्वविद्यालय तीन तलाक पर रोक लगाने वाले मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार सरंक्षण) अधिनियम को एलएलबी और एलएलएम के पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन गया है - महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय

हिमाचल सामान्य ज्ञान

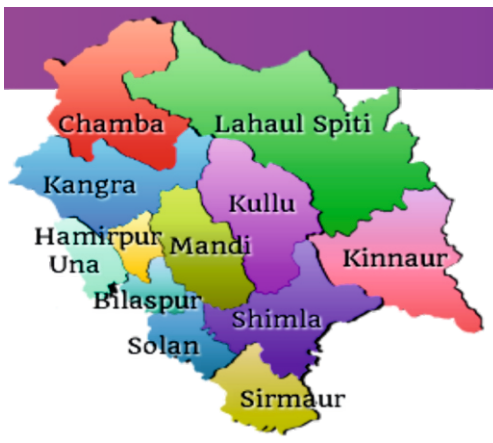

- हिमाचल सरकार पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस नदी पर स्थापित करेगी - सतलुज, 15 मेगावाट
- नीति आयोग के स्कूल एजूकेशन क्वालिटी इंडेक्स सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त है - 9वां
- हिमाचल में सबसे ज्यादा वन किस जिले में है - चंबा
- क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है - ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क
- हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष मानसून के दौरान सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर दर्ज हुई - कांगड़ा, 1210 मिलीलीटर
- मंडी में कहां पर शिवधाम पर्यटक स्थल स्थापित किया जाएगा - कंगनधार, एडीबी के सहयोग से
- हिमाचल सरकार कितने इको टूरिज्म साइट्स विकसित करेगी - 12
- राजस्व रिकार्ड ऑनलाइन करने वाला हिमाचल भारत का कौन सा राज्य बना है - 7 वां
- धर्मशाला कारागार का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा - लाला लाजपत राय
- सौर ऊर्जा बाड़बंदी कि लिए कितना अनुदान दिया जाता है - 80 फीसदी (एकल) 85 फीसदी (सामुहिक)
- हिमाचल में न्यायिक आयुक्त कोर्ट कब स्थापित किया गया था - 1948 में
- शिमला कब से कब तक निर्वासित बर्मा सरकार का मुख्यालय था - 1942 से 1945
- आंगनबाड़ी केंद्रों के बेहतर प्रदर्शन के लिए कन्वर्जेंस पुरस्कार किसे मिला - मंडी और कल्पा
- कैंपा की फुल फोर्म क्या है - कंपनसेटरी एफोरस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ऑथॉरिटी
- स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड किस विभाग को दिया गया - महिला एवं बाल विकास विभाग

आर्थिक सर्वेक्षण

- हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर 16 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का मवेशी चारा संयत्र स्थित है - भोर, जिला मंडी
- 2017–18 में राज्य के कुल सकल घरेलु उत्पाद में माध्यमिक क्षेत्र का योगदान कितना है - 49.20 प्रतिशत
- वन समृद्धि जन समृद्धि योजना शुरूआती तौर पर कितने जिलों में शुरू की गई है - सात
- 2018–19 में अनुमानित दूध उत्पादन (लाख टन) में कितना रहा - 14.71
- हिमाचल में किस स्थान पर याक प्रजनन फार्म स्थापित किया गया है - लारी - लाहौल स्पीति
- 2018–19 में हिमाचल की अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है - 7.3 प्रतिशत
- 2018–19 में हिमाचल में वनों द्वारा कवर किया गया कुल क्षेत्रफल - 37,947 सक्वेयर किलोमीटर
- छोटे और सीमांत किसानों को चाय की खेती के लिए कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है - 50 प्रतिशत
- मछली उत्पादन के लिए किन दो स्थानों पर कार्प फीड मिल स्थापित की गई है - बिलासपुर और कांगड़ा
- उत्तम चारा उत्पादन के तहत कितना हैक्टेयर क्षेत्र लाया जाना है - 25 हजार हैक्टेयर
- हिमाचल में चूजों के उत्पादन के लिए हैचरी किस स्थान पर है - सुंदरनगर और नाहन
- 2017–18 में खाद्यान उत्पादन कितना रहा - 15.31 लाख मीट्रिक टन
- अटल आदर्श विद्यालय योजना कहां से शुरू की गई - बरठीं

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना 2019

यह एक बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो हिमाचल प्रदेश में रहते है..हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में 'हिमाचल प्रदेश सहारा योजना 2019' का शुभारंभ किया है। Himachal Pradesh Sahara Yojana 2019 योजना के तहत गरीब लोग जो अस्पताल में इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी और इस योजना में राज्य सरकार ने गरीब लोगों को 2000/ प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, इस प्रदान की गई आर्थिक सहायता से गरीब लोग पैरलिसिस, कैंसर, पारकिनसन, मस्क्युलर डाइस्ट्रफी, थैलेसेमिया, हेमोफिलिया, लिवर फेल्यूर बीमारी का इलाज करा सके।

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना 2019 के लाभ

इस योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवारों के लोगों को दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम है।

इस योजना के तहत, 2000/- प्रति माह राज्य सरकार द्वारा उपचार के लिए वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा।

पहले चरण में, इस योजना के तहत लगभग 6000 लोगों को शामिल किया जाएगा।

योजना के अनुसार, लाभार्थी के बैंक खाते में निर्धारित वित्तीय सहायता की राशि जमा की जाएगी ।

वे सात बीमारी जिन के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी

पैरलिसिस (Paralysis)
कैंसर (Cancer)
पारकिनसन (Parkinson)
मस्क्युलर डाइस्ट्रफी (muscular dystrophy)
थैलेसेमियां (sthalassemi)
हेमोफिलिया (hemophilia)
लिवर फेल्यूर (liver failure)

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के आवेदन सम्बन्धी आवश्यक दस्तावेज

पहचान पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
आय प्रमाण-पत्र
ट्रीटमेंट रिकॉर्ड
बैंक डिटेल

हिमाचल प्रदेश सहारा के लिए अप्लाई कैसे करें

आप इस योजना का चीफ मेडिकल ऑफिसर के कार्यालय में जाकर प्राप्त कर सकते हैं ।

इस फॉर्म को प्राप्त करने के बाद आप सभी जरूरी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ जोड़ने होंगें और जिला चिकित्सक अधिकारी के पास जमा करवाने होंगें ।

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना का लाभ पाने के लिए आपको Online आवेदन करने की कोई आवश्यकता नही है आपको ज़िला चिकित्सक अधिकारी के कार्यालय में सारे कागजात जमा करवाने हैं ।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

क्या हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के उद्देश्य

- दुधारू पशुओं के स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण
- स्वदेशी पशु के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम
- इससे पशुओं में अनुवांशिक सुधार और पशुओं की संख्या में वृद्धि संभव होगी
- दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश
- साहीवाल, राठी, देउनी, थारपारकर, रेड सिन्धी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए बाकी नस्लों को उन्नत बनाना
- प्राकृतिक सेवा के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांड का वितरण
- सरकार ने इस परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2014/15 में 150 करोड़ रुपये आवंटित किए थे

इन कामों के लिए किया जाता है धन का आवंटन

- धन का आवंटन गोकुल मिशन के तहत एकीकृत स्वदेशी पशु केंद्र मसलन गोकुल ग्राम बनाना।
- उच्च आनुवांशिक क्षमता वाले स्वदेशी नस्ल के संरक्षण के लिए बुल मदर फार्म्स को मजबूत करना प्रजनन तंत्र में क्षेत्र प्रदर्शन रिकॉर्डिंग (एफपीआर यानी FPR) की स्थापना
- जर्मप्लाज्म संरक्षण संस्थानों संगठनों को मदद देना
- बड़ी आबादी के साथ स्वदेशी नस्ल के लिए वंशावरी चुनाव कार्यक्रम
- ब्रीडर्स सोसायटी, गोपालन संघ बनाना
- स्वदेशी नस्ल के कुलीन पशुओं को रखने वाले किसानों को मदद
- बछिया पालन कार्यक्रम, किसानों को पुरस्कार (गोपाल रत्न) और ब्रीडर्स सोसायटी (कामधेनु) बनाना

स्वदेशी नस्ल के लिए समय-समय दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता

स्वदेशी पशु विकास कार्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों में काम करने वाले तकनीकी और गैर-तकनीकि लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

गोकुल ग्राम क्या है

गोकुल ग्राम देशी पशु केंद्र और अधिनियम स्वदेशी नस्लों के विकास के लिए केंद्र के रूप में काम कर रहा है और गोकुल ग्राम मूल प्रजनन इलाकों और शहरी आवास के लिए मवेशियों के पास महानगरों में स्थापित है।

गोकुल ग्राम किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र में आधुनिक सुविधाएं देता है। 1000 जानवरों की क्षमता वाले इन ग्रामों में दुग्ध उत्पादक और अनुत्पादक पशुओं का अनुपात 60:40 का है। गोकुल ग्राम पशुओं के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए घर में चारा उत्पादित करने के लिए बनाये गए हैं।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यान्वयन राष्ट्रीय गोकुल मिशन राज्यों के पशुधन विकास बोर्ड जैसे संस्थानों के माध्यम से चलाया जाता है। इस योजना के लिए फंड एकीकृत स्वदेशी पशु केंद्र, गोकुल ग्राम की स्थापना के लिए दिया जाता है। राज्य गौसेवा आयोग को एसआईए (एलडीबी) के प्रस्ताव को प्रायोजित करने और इन प्रायोजित प्रस्तावों की निगरानी का आदेश दिया गया है। स्वदेशी पशु विभाग में सर्वश्रेष्ठ जर्मप्लाज्म के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एजेंसियों मसलन, सीसीबीएफ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि या पशुपालन विश्वविद्यालय, कॉलेज, एनजीओ, सहकारी समितियां और गौशालाएं इसमें प्रतिभागी एजेंसियां हैं।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन का आर्थिक उद्देश्य

गोकुल ग्राम वास्तव में एक आर्थिक संस्थान की तर्ज पर विकसित किया गया है, इसमें गौ उत्पादों की बिक्री के जरिए आर्थिक संसाधन पैदा किये जा रहे है।

दूध जैविक खाद , केंचुआ खाद, गौ मूत्र डिस्टिलेट घरेलू खपत के लिए बायो गैस से बिजली का उत्पादन, पशु उत्पादों की बिक्री जैसी गतिविधियां गोकुल ग्राम को आत्मनिर्भर संगठन बना रही हैं।

स्त्री स्वाभिमान योजना

- महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए सरकार की तरफ से योजना शुरू की गई है। इसका नाम है स्त्री स्वाभिमान योजना। हमारे देश में आज भी कई महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक नहीं है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को मासिक धर्म के समय अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरुक बनाना है। इस योजना से ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मासिक धर्म के समय सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- स्त्री स्वाभिमान योजना 27 जनवरी, 2018 को लॉन्च की गई।
- स्त्री स्वाभिमान योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं को ईको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन वितरित करना है।
- खासकर ग्रामीण इलाकों की लड़कियों और महिलाओं को यह सैनिटरी नैपकिन बहुत ही कम मूल्य पर दिए जाते हैं।
- स्त्री स्वाभिमान योजना के तहत देश में बहुत सी जगहों पर छोटी-छोटी निर्माण के लिए यूनिट्स लगाई जा रही है। इसमें अधिकतर महिलाएं ही शामिल हैं।
- ऐसे में महिलाओं को इन निर्माण यूनिट में रोजगार भी उपलब्ध हो रहा हैं।
- **लाभ**
- मासिक धर्म के समय सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी ।
- सरकारी स्कूल की सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन प्रदान करेगी ।
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा ।
- महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जाएगी।
- यह योजना देश भर तक पहुंचाई जा रही है ।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

CSR प्रोजेक्ट: कॉरपोरेट की मदद से कितने सुधरे देश के हालात?

कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (**CSR**) नियम को बने 3 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन खर्च के हिसाब में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। इसके तहत सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च हुआ है। देश में महाराष्ट्र ऐसा राज्य रहा, जहां सबसे ज्यादा **CSR** फंड खर्च हुआ।

1 अप्रैल 2014 से कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (**CSR**) प्रभाव में आया। जहां 500 करोड़ नेटवर्थ या 1000 करोड़ राजस्व वाली कंपनियों को अपने मुनाफे का 2 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और स्वच्छता सुधार पर खर्च करना होगा। इनमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष 100 कंपनियां शामिल हैं। इसको अनुसूची **VII** के अंतर्गत रखा

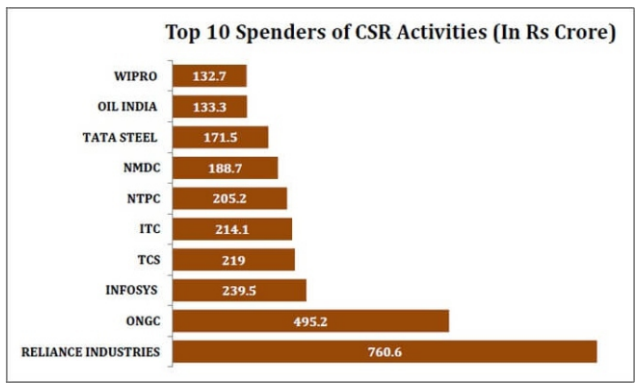

गया।

Goodera की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय साल 2017 में सीएसआर योजना के तहत 92 कंपनियों ने 18 सितंबर तक 6810 करोड़ रुपए सामाजिक सुधार के लिए खर्च किए। बाकी 8 कंपनियों ने अपना डाटा साझा नहीं किया।

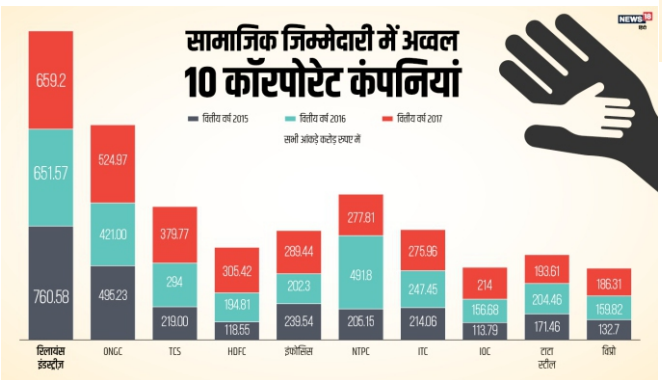

आंकड़ों के मुताबिक शीर्ष 10 कंपनियों ने 3307 करोड़ खर्च किए, जो बाकी कंपनियों के कुल खर्च का 50 प्रतिशत है। इस वित्तीय वर्ष कुल CSR खर्च की ग्रोथ में 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कि कंपनियों के मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई है। दूसरा कारण 16 प्रतिशत कंपनियों ने अपने खर्च में कमी की है।

पब्लिक सेक्टर का फोकस

CSR के लिए जारी करने वाली शीर्ष 92 कंपनियों में से 15 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। कुल फंड 6810 करोड़ में उनकी हिस्सेदारी 1996 करोड़ करीब 15 प्रतिशत की रही। इस वित्तीय वर्ष PSU का निर्धारित फंड 1 प्रतिशत ज्यादा था लेकिन खर्च के मामले में ये 9 प्रतिशत घटा है।

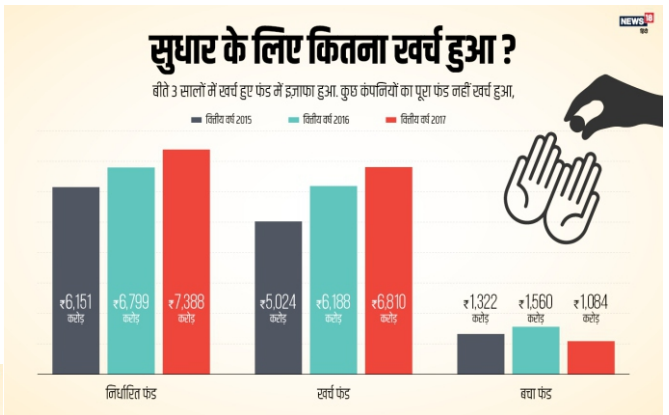

विशेषज्ञों के मुताबिक अगर हालातों में सुधार करना है तो उन्हें सीमित लेकिन सामरिक प्रोजेक्टों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। प्राइवेट कंपनियों ने जहां 14 प्रोजेक्टों की जिम्मेदारी तो वहीं PSU की संख्या 26 रही जिस कारण फोकस करने में समस्या पैदा हुई।

किन क्षेत्रों में हुआ सर्वाधिक खर्च

शिक्षा और व्यवसायिक स्किल में ै के तहत सबसे ज़्यादा बजट खर्च किया गया। 2191.20 करोड़ के साथ यह क्षेत्र पहले स्थान पर रहा। जबकि गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य सुधार के लिए कंपनियों ने कुल 1714.89 करोड़ रुपए खर्च किए। ये सारे आंकड़े वित्तीय वर्ष 2017 के हैं। सर्वाधिक खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर ग्रामीण विकास रहा। जहां कंपनियों ने कुल 886.45 करोड़ रुपए खर्च किए। अक्सर कहा भी जाता रहा है कि गांव के हालात सुधारकर ही देश की नींव मजबूत की जा सकती है। पर्यावरण सुधार की बात की जाए तो CSR नीति की तहत 764.45 करोड़ रुपए निजी और पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनियों ने खर्च किए।

कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी क्या है

जैसा कि हमें पता है कि कम्पनियाँ किसी उत्पाद को बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती हैं, प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं और अपनी मुनाफा कमाती हैं लेकिन इस खराब प्रदूषण का नुकसान समाज में रहने वाले विभिन्न लोगों को उठाना पड़ता है। क्योंकि इन कंपनियों की उत्पादक गतिविधियों के कारण ही उन्हें प्रदूषित हवा और पानी का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन इन प्रभावित लोगों को कंपनियों की तरफ से किसी भी तरह का सीधे तौर पर मुआवजा नही दिया जाता है। इस कारण ही भारत सहित पूरे विश्व में कंपनियों के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया कि वे अपनी आमदनी का कुछ भाग उन लोगों के कल्याण पर भी करें जिनके कारण उन्हें असुविधा हुई है। इसे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी (CSR) कहा जाता है।

C.S.R. में क्या क्या गतिविधियाँ की जा सकती हैं

C.S.R. के अंतर्गत कंपनियों को बाध्य रूप से उन गतिविधियों में हिस्सा लेना पड़ता है जो कि समाज के पिछड़े या वंचित वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए जरूरी हों।

इसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल होती हैं :

1. भूख, गरीबी और कुपोषण को खत्म करना
2. शिक्षा को बढ़ावा देना
3. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधारना
4. पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना
5. सशस्त्र बलों के लाभ के लिए उपाय
6. खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना
7. राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण
8. प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय राहत में योगदान
9. स्लम क्षेत्र का विकास करना
10. स्कूलों में शौचालय का निर्माण
11. राहत पुनर्वास और पुनर्संरचना कार्याकलापों सहित आपदा प्रबधंन

किस क्षेत्र पर कितना खर्च हुआ है?

1. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 3117 करोड़ रुपये
2. शिक्षा 3073 करोड़ रुपये
3. ग्रामीण विकास 1051 करोड़ रुपये

4. पर्यावरण 923 करोड़ रुपये
5. स्वच्छ भारत कोष 355 करोड़ रुपये

एक सर्वे के अनुसार, वर्ष 2016 में भारत की 99 प्रतिशत कंपनियों ने CSR नियमों का पालन किया है, इसके अलावा सिर्फ जापान और इंग्लैंड की कंपनियों ने 99 प्रतिशत का आंकड़ा छुआ है।

भारत की कंपनियों द्वारा समाज के निचले तबके के कल्याण को बढ़ावा देना कंपनियों और सरकार दोनों के लिए दोनों हाथों में लड्डू होने जैसा है। CSR में खर्च होने के जहाँ एक तरफ लोगों के कल्याण के लिए होने वाले खर्च से सरकर को कुछ राहत मिलती है वहीं दूसरी तरफ लोगों की नजर में कंपनियों की इमेज भी एक अच्छी कंपनी की बनती है जिससे कि कंपनी को अपने उत्पादों को बेचने में आसानी होती है।

हिमाचल प्रदेश मे मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना

द रीव टाइम्स ब्यूरो : महिला और बाल विकास मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों का कल्याण है। अनाथ बच्चा वह है जिसका माता पिता मृत, अज्ञात है, या उसे स्थायी रूप से त्याग दिया है, इस तरह के बच्चों की देखभाल और रखरखाव के लिए यह योजना हैं। इस योजना के तहत हिमाचल सरकार बच्चों को मुफ्त आश्रय, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त भोजन और पेशेवर मार्गदर्शन और कई अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई हैं। राज्य में सभी अनाथ बच्चों की सहायता करने के लिए, बाल उद्धार योजना का हिस्सा बनने और योजना द्वारा प्रदान किए गए सभी लाभ प्राप्त करने के लिए रिश्तेदार मदत करें। महिलाओं और बाल विकास कार्यालय में अधिक विवरण और आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना के लाभ:

अनाथ बच्चों को कई लाभ प्रदान करने के लिए बाल कल्याण योजना

इस योजना के तहत, हिमाचल सरकार ने अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, आवास, खाना, व्यावसायिक मार्गदर्शन और कई अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई हैं

मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना के लिए आवेदन करने की आवश्यक पात्रता और शर्त

- हिमाचल प्रदेश के अनाथ लड़की या लड़के

मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना के लिए आवेदन करने वाले आवश्यक दस्तावेज:

- पहचान प्रमाण
- आवेदन प्त्र (कार्यालय में उपलब्ध)
- निवासी प्रमाण

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

118 साल से कभी फ्यूज, नहीं हुआ बल्ब

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आमतौर पर कोई भी बिजली वाला बल्ब खरीदने पर कंपनियां उस पर एक साल या मुश्किल से दो-तीन साल की गारंटी देती हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई बल्ब लगातार दो-तीन साल तक जलता रहे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा बल्ब भी है, जो 118 साल से लगातार जल रहा है। ये बल्ब आज तक फ्यूज नहीं हुआ। इस अजूबे बल्ब को सेंटेनियल नाम से जाना जाता है। कैलिफोर्निया के लिवरमोर शहर के दमकल केंद्र में लगे इस बल्ब को शेल्बी इल्क्ट्रॉनिक कंपनी ने बनाया था, जिसे वर्ष 1901 में पहली बार जलाया गया था। तब से लेकर आज तक यह बल्ब जल ही रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 1937 में बिजली का तार बदलने के लिए इस बल्ब को पहली बार बंद किया गया था और तार बदलने के बाद उसे फिर से जला दिया गया था। इस बल्ब का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इस बल्ब की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाती है। चार वॉट बिजली से चल रहा ये बल्ब 24 घंटे जलता रहता है। साल 2001 में इस बल्ब का 100वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया था, जिसमें संगीत पार्टी का भी आयोजन किया गया । साल 2013 में यह बल्ब अपने आप बंद हो गया था, तब लोगों को लगा था कि शायद बल्ब फ्यूज हो गया, लेकिन जब जांच की गई तो तार में खराबी निकली। इसके बाद तार को फिर से बदल दिया गया और बल्ब फिर जलने लगा।

54 घंटे में चार बार तैरकर पार किया इंग्लिश चैनल ऐसा करने वाली बनी दुनिया की पहली महिला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इंग्लिश चैनल को पार करना आसान नहीं होता है। इसमें दुनिया के अच्छे से अच्छे तैराकों के भी पसीने छूट जाते हैं, लेकिन अमेरिका की एक महिला ने बिना रूके चार बार तैरकर इंग्लिश चैनल को पार किया और एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। सारा थॉमस नाम की महिला ने इंग्लिश चैनल को चार बार पार करने में महज 54 घंटे का समय लिया। इस दौरान उन्होंने कुल 209 किलोमीटर की दूरी तय की। सारा ने इंग्लैंड से तैरना शुरू किया था और अपना आखिरी चक्कर फ्रांस में खत्म किया। हैरानी की बात तो ये है कि 37 वर्षीय सारा को पहले ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन पिछले साल ही उन्होंने कैंसर को हराकर एक नई जिंदगी हासिल की। इसके बाद उन्होंने तैराकी में ये अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनाया।

सारा ने बताया, तैरने के दौरान मुझे कई बार जेलीफिश का भी सामना करना पड़ा। इसके अलावा पानी भी काफी ठंडा था। हालांकि यह उतना नहीं था, जितना मैंने सोचा था। सारा ने अपनी तैराकी कैंसर पीड़ितों को समर्पित की है। सारा ने लगातार तैराकी के दौरान नींद की भरपाई करने के लिए इलेक्ट्रोल और कैफीन युक्त तरल पदार्थ लिया। उन्होंने जैसे ही अपनी तैराकी पूरी की, लोगों ने उन्हें शैंपेन की बोतल और चॉकलेट देकर बधाई दी।

लकड़ी से बनी है 24 मंजिला इमारत, दूर-दूर से देखने आते हैं लोग

द रीव टाइम्स ब्यूरो

किसी घर को बनाने में सीमेंट, पत्थर, रेत और न जाने क्या-क्या इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक इमारत को बनाने में उसके पिलरों को छोड़ कर पूरी तरह से सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। 24 मंजिला इस इमारत की ऊंचाई 99.9 मीटर है। लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए इतनी ऊंची इमारत का निर्माण करना अपने आप में एक अनोखा काम है। पूरी तरह से इकोफ्रेंडली इस लकड़ी की इमारत में 150 से अधिक कमरे बनाए गए हैं। बिल्डिंग की मजबूती के लिए देवदार की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस इमारत की दीवार से लेकर छत तक को भी लकड़ी से ही तैयार किया गया है। चीन के गुइझोई प्रांत के यिंगशान शहर में बनी यह इमारत फिलहाल तो खाली पड़ी है, लेकिन पर्यटकों के देखने के लिए इसे खोल दिया गया है। इस इमारत को देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक आते हैं। उनके लिए यह इमारत किसी अजूबे से कम नहीं है। लकड़ी से बनी इस इमारत का निर्माण आर्किटेक्ट सुइ हैंग ने किया है। सुइ हैंग के अनुसार, इस इमारत को बनाने में दो साल का समय लगा है। सुइ हैंग ने बताया कि इस इमारत की डिजाइन तीन साल पहले ही बना ली गई थी, लेकिन इसकी रुपरेखा तैयार करने में ही करीब एक साल से अधिक का समय लग गया।

दुनिया की सबसे महंगी जेल, जहां सिर्फ एक कैदी पर सालाना खर्च होते हैं 93 करोड़ रुपये

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आमतौर पर जब भी जेल का नाम जेहन में आता है तो मन में कई तरह के सवाल कौंध जाते हैं। मसलन वहां की सुरक्षा, कैदियों के खाने-पीने की व्यवस्था कैसी होगी। लेकिन क्यूबा में एक ऐसी जेल है, जहां इन सब बातों को सोचने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि यहां सिर्फ एक कैदी पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। यही वजह है कि यह जेल दुनिया की सबसे महंगी जेल मानी जाती है।इस जेल का नाम है ग्वांतानमो बे जेल। इस जेल का ये नाम इसलिए पड़ा, क्योंकि यह ग्वांतानमो खाड़ी के तट पर स्थित है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस जेल में फिलहाल 40 कैदी हैं और हर कैदी पर सालाना करीब 93 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जेल में करीब 1800 सैनिक तैनात हैं। यहां सिर्फ एक कैदी पर करीब 45 सैनिकों की नियुक्ति है।

जेल की सुरक्षा में तैनात सैनिकों पर हर साल करीब 3900 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस जेल में कैदियों को इतनी सुरक्षा क्यों दी जाती है? तो आपको बता दें कि यहां कई ऐसे अपराधियों को रखा गया है, जो बेहद ही खतरनाक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 9/11 हमले का मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद भी इसी जेल में बंद है।

रहस्य जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए

द रीव टाइम्स ब्यूरो

यह दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। विज्ञान के लिए ये उपलब्धि है कि कुछ रहस्यों को सुलझा लिया गया है, लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं, जिन्हें सालों से वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यों से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पेरु में एक पौराणिक मंदिर है साकसेगेमन मंदिर। इस मंदिर के परिसर में बड़े-बड़े पत्थरों की एक दीवार है। इसकी सबसे खास बात ये है कि सभी पत्थर आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन आज तक ये रहस्य ही बना हुआ है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया गया था और हजारों साल पहले ये पत्थर इतनी बारीकी से कैसे तराशा गया होगा और एक-दूसरे के ऊपर रखा गया होगा।

बोलिविया में एक जगह है टिवानाकु, जिसे रहस्यमयी शहर कहा जाता है। कहते हैं कि हजारों साल पहले यहां एक आबाद शहर हुआ करता था। यहां एक दरवाजा है, जिसे गेट अहफ सन कहा जाता है, वो आज भी रहस्य ही बना हुआ है। वैज्ञानिकों को लगता है कि इस गेट की मदद से उस समय ग्रहों की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता होगा। हालांकि इसके बारे में सटीक जानकारी किसी को भी नहीं पता। जापान में एक गोताखोर किहाचिरो अराताके को समुद्र में डूबे एक विशाल ढांचे की खोज की थी, जिसे योनागुनी का डूबा शहर कहते हैं। माना जाता है कि यह ढांचा 10 हजार साल पहले डूब गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पाषाण युग के बाद इंसान जब पहली बार गुफाओं से बाहर निकले तो उन्होंने ऐसा ढांचा बनाया होगा। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, सच्चाई नहीं। कोस्टा रिका में पत्थर की कई विशाल गेंदे हैं, जो साल 1930 में पौधों की रोपाई के दौरान मिली थीं। खास बात ये है कि पत्थर की ये गेंदें बिल्कुल गोल हैं। अब इन गेंदों को किसने बनाया, क्यों बनाया, ये रहस्य ही है। पौराणिक कथाओं की मानें तो इन गेंदों में सोना था। मिस्त्र में खुदाई के दौरान एक विशाल स्तंभ मिला था। 42 मीटर लंबा यह स्तंभ करीब 1200 टन वजनी है। इतिहासकारों की मानें तो निर्माण के दौरान पत्थर में दरार आने की वजह से इसे अधूरा छोड़ दिया गया, लेकिन ये बात अब तक एक रहस्य ही है कि इतना विशाल स्तंभ कैसे उठाया जाता?

धरती पर देखना है स्वर्ग तो जाना पड़ेगा जमीन के अंदर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

स्वर्ग जाने की इच्छा किसकी नहीं होती, लेकिन लोग सोचते हैं कि धरती पर तो ये संभव है नहीं, क्योंकि स्वर्ग तो धरती से दूर कहीं आसमान में है, जिसका पता किसी के पास नहीं है। धरती पर ही कुछ ऐसी जगहें हैं जो स्वर्ग से बिल्कुल भी कम नहीं है।

एंजेल शॉवर्स :

अमेरिका के मिसौरी प्रांत में स्थित एक गुफा को 1880 के दशक में खोजा गया था, जिसका नाम ओजार्क्स कवेर्न्स है। यह गुफा एंजेल शॉवर्स के नाम से मशहूर फुहारों के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा की छत से पानी की कई धाराएं केल्साइट के बने बाथटब जैसी आकृति में गिरती हुई दिखती हैं। इस मनमोहक नजारे को देखकर ऐसा लगता है मानो आप स्वर्ग में आ गए हों। अलग-अलग रंगों की रोशनी से सजी लाइमस्टोन की यह गुफा करीब 180 मिलियन साल पुरानी है।

रीड फ्लूट गुफा: चीन में स्थित इस गुफा को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जापानी सैनिक द्वारा खोजा गया था। इसे रीड फ्लूट गुफा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग होगा तो कुछ इसी तरह का होगा।

प्यूर्टो प्रिंसेसा की भूमिगत नदी: यह दुनिया की सबसे लंबी भूमिगत नदी है। इसे प्यूर्टो प्रिंसेसा की भूमिगत नदी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2012 में दुनिया के सात नये अजूबों में शामिल की गई यह भूमिगत नदी फिलीपींस के पलावन द्वीप पर स्थित है। यहां का नजारा बिल्कुल ही अनोखा होता है।

सलीना तुरडा की खदान रोमानिया के ट्रांसिल्वानिया के करीब स्थित नमक की यह खदान साल 1992 में आम पर्यटकों के खोली गई थी। तब से लेकर अब तक 20 लाख से भी ज्यादा पर्यटक अपनी आंखों से इस खूबसूरत खदान को निहार चुके हैं। इसे सलीना तुरडा के नाम से जाना जाता है।

ग्लोवॉर्म के नाम से पहचानी जाने वाली यह खास फंगस केवल न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है। ग्लोवॉर्म की मौजूदगी के चलते गुफा में हमेशा एक खूबसूरत चमक फैली रहती है। इसका नाम वाइटोमो ग्लोवॉर्म गुफा है।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

संगीत की अनोखी प्रतियोगिता, तीन देशों से पक्षी पहुंचेंगे गाना गाने

द रीव टाइम्स ब्यूरो

संगीत प्रतियोगिता के बारे में आपने जरूर सुना और देखा होगा। एक से बढ़कर एक संगीतकार प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। ऐसी ही एक संगीत प्रतियोगिता चल रही है, लेकिन इंसानों की नहीं बल्कि पक्षियों की। पक्षियों की संगीत प्रतियोगिता के बारे में सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यह प्रतियोगिता चल रही है। इस प्रतियोगिता में पक्षी गीत गाते हैं। पक्षियों को उनके बुद्धिमत्ता और गाने के आधार पर नंबर मिलते हैं। थाईलैंड के नारथीवाट में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। बता दें कि इस प्रतियोगिता में थाइलैंड के अलावा सिंगापुर और मलेशिया के 1800 से ज्यादा पक्षी हिस्सा ले रहे हैं। चार माह की ट्रेनिंग के बाद से पक्षी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। थाइलैंड में यह प्रतियोगिता पिछले साल भी आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता की तैयारी पक्षियों के मालिक 4 माह पहले से ही इस प्रतियोगिता की तैयारी कराना शुरू कर देते हैं। इस प्रतियोगिता में बुलबुल, तोते, कबूतर और अन्य छोटे पक्षी शामिल होते हैं। इस प्रतियोगिता के चार राउंड होते हैं। प्रत्येक राउंड में पक्षियों को कम से कम तीन बार 25 सेकंड तक गाना होता है।

विजेता को मिलेगा डेढ़ लाख का इनाम

प्रतियोगिता के दौरान पक्षियों को 15 फीट ऊंचे खंभे पर पिंजरे में बिठाकर लटका दिया जाता है। इसके बाद बारी-बारी से इन पक्षियों को उतरकर गाने को कहा जाता है। इस प्रतियोगिता में जज बारी-बारी से सभी पक्षियों की गीतों को सुनते हैं और नंबर देते हैं। जिस पक्षी को सबसे ज्यादा नंबर मिलता है वो विजेता बनता है और उसे इनाम मिलता है। इस बार विजेता को डेढ़ लाख रुपये इनाम में दिए जाएंगे। जबकि पिछले साल 70 हजार रुपये दिए गए थे।

द रीव टाइम्स
संस्थापक: डॉ एल.सी. शर्मा
प्रकाशक: आईआईआरडी काम्पलेक्स, बाईपास रोड शनान, सन्जौली शिमला-6 हि.प्र.
द रीव टाइम्स के लिए मुद्रक प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस, सायबू निवास समीप सेक्टर-2, बस स्टैंड, मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित
संपादक: हेम राज चौहान
फोन न. : 0177 2640761
आर.एन.आई. रिफ्रेंस नं. 1328500
टाइटल कोड : HPBIL00313
पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं. HP/129/SML/2019-2021
E-mail : hem.raj@iirdshimla.org
Website : www.therievtimes.com

आवश्यक सूचना
हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के/लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा। इच्छुक शीघ्र ही संपर्क करें।

द रीव टाइम्स
दूरभाष : 9418404334
Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org